

'ये गोलाद्ध हमारा इलाका, नहीं चलने देंगे किसी का दबदबा'

राष्ट्रबाण
नई दिल्ली. वेनेजुएला से टकराव के बीच संयुक्त राष्ट्र में अमेरिका के राजदूत माइक वाल्टज ने स्पष्ट कहा है कि पृथ्वी का पश्चिमी गोलाई हमारा इलाका है और अमेरिका इस क्षेत्र में किसी की दादागिरी नहीं चलने देगा। राजदूत माइक वाल्टज ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर वेनेजुएला में हुए अमेरिकी ऑपरेशन की जानकारी देते हुए ऐसा कहा.माइक वाल्टज ने साफ साफ कहा कि हम पश्चिमी गोलाई को अपने देश के दुश्मनों, हमारे कॉम्प्यूटिटर और संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रतिद्वंद्वियों के लिए ऑपरेशन के बेस के तौर पर इस्तेमाल नहीं होने देंगे. संयुक्त राज्य अमेरिका का ये मैसेज रूस और चीन के लिए स्पष्ट संदेश है, जो देश व्यापारिक संबंधों के तहत वेनेजुएला से अपने संबंध ठीक कर रहे थे. यूएन में अमेरिका के राजदूत माइक वाल्टज ये बयान दे रहे थे उसी वकत संयुक्त राष्ट्र में बैठे वेनेजुएला के राजदूत गुरसे से उठल रहे थे. अमेरिका ने अपने ऑपरेशन के बारे में क्या क्या बताया. ये बताने से पहले

करूर भगदड़ में एक्टर विजय से होगी पूछताछ

CBI ने TVK प्रमुख को किया समन
राष्ट्रबाण
दिल्ली. सेंट्रल ब्यूरो ऑफ़ इन्वे-स्टिगेशन (CBI) ने एक्टर-पॉलि-टिशियन और तमिलनाा वेद्री कन्नम (TVK) के संस्थापक विजय को करूर भगदड़ मामले के सिलसिले में 12 जनवरी को पेश होने के लिए समन जारी किया है. यह भगदड़ 27 सितंबर 2025 को करूर ज़िले के वेलुस्वामीपुरम में TVK की एक राजनीतिक रैली के दौरान हुई थी, जब भारी भीड़ की वजह से यह घटना जानलेवा हो गई थी. इस घटना में 41 लोगों की जान चली गई थी और दर्जनों लोग घायल हो गए थे, क्योंकि विजय की स्पीच के लिए बड़ी तादाद में समर्थक इकट्ठा हुए थे.यह

पूर्व CM विलासराव देशमुख पर BJP चीफ का विवादित बयान

राष्ट्रबाण
मुंबई. भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) की महाराष्ट्र इकाई के अध्यक्ष रवींद्र चव्हाण ने पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख को लेकर विवादित टिप्पणी की थी. इस पर रितेश देशमुख ने प्रतिक्रिया दी थी. उन्होंने कहा था कि उनके पिता का नाम कोई नहीं मिटा सकता. इस बीच रवींद्र चव्हाण ने मंगलवार को कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख की यादों को 'मिटाने' संबंधी उनकी टिप्पणी राजनीतिक रूप से प्रेरित नहीं थी और अगर इससे दिवंगत नेता के पुत्र की भावनाएं आहत हुईं हैं तो वह उनसे माफ़ी मांगते हैं. लातूर महानगर पालिका चुनावों से पहले चव्हाण ने सोमवार (5 जनवरी) को कहा था कि दिवंगत

BMC चुनाव जीते तो क्या करेंगे?

पहली बार उम्मीदवारों से नॉमिनेशन फॉर्म में लिखवाया गया प्लान पर निबंध
राष्ट्रबाण
मुंबई. बीएमसी आम चुनाव के इतिहास में पहली बार उम्मीदवारों को नामांकन पत्र और शपथ पत्र दाखिल करने के अलावा और भी कुछ करने को कहा गया. नामांकन पत्र जमा करने वाले सभी 2516 उम्मीदवारों को एक निबंध लिखना अनिवार्य था. निर्देशानुसार निबंध 100 से 500 शब्दों के बीच होना चाहिए. इस निबंध में उन्हें यह बताया था कि निर्वाचित होने पर वे अपने स्थानीय क्षेत्रों का विकास कैसे करेंगे. राज्य चुनाव आयोग के सचिव सुरेश काकानी ने कहा कि यह प्रारंभिक 2018 में लागू किया गया था और तब से उपचुनावों में इसका उपयोग किया जाता रहा है. लेकिन इनमें बड़े पैमाने के आम नगर निगम चुनाव में पहले कभी नहीं किया गया.

मादुरो पर अमेरिका ने चीन-रूस को दिखाई आंख

पश्चिमी गोलाई क्या है

पश्चिमी गोलाई पृथ्वी का वह आधा भाग है जो ग्राहम मेरिडियन (0° देशांतर, जो ग्रीनविच से गुजरती है) के पश्चिम में और 180° देशांतर के पूर्व में स्थित है. सामान्य भाषा में कहे तो यह पृथ्वी को 2 भागों में, पूर्वी और पश्चिमी गोलाई में विभाजित करेा का भौगोलिक तरीका है. इस हिस्से में मुख्य रूप से उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और आसपास के महासागर इस गोलाई में आते हैं. इसमें पूरे नॉर्थ अमेरिका (कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको आदि) और साउथ अमेरिका (ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली आदि) के देश शामिल हैं. त्कनीकी रूप से कुछ हिस्से यूरोप (जैसे आइसलैंड, पश्चिमी ग्रीटन), आफ्रीका के पश्चिमी भाग, ओशिनिया के कुछ द्वीप और अंटार्कटिका का भाग भी आते हैं. लेकिन आम बोलचाल और भूगोल में पश्चिमी गोलाई का मतलब मुख्यतः अमेरिकी महाद्वीप से होता है.

UN में वेनेजुएला को लेकर क्या क्या बोला अमेरिका

इस तरह से अमेरिका ने वेनेजुएला के खिलाफ ऑपरेशन कर इस खंय को इस पूरे परिया का स्वयंभू मालिक घोषित कर दिया है .अमेरिकी राजदूत वाल्टज ने कहा कि मादुरो सिर्फ एक आरोपी इग तस्कर नहीं है. वह एक नाजायज तथाकथित राष्ट्रपति था. वह कोई राष्ट्राध्यक्ष नहीं था.

पश्चिमी गोलाई क्या है इसे समझना जरूरी है.अमेरिका ने UN में आरोप लगाया कि वर्षों से मादुरो और उसके

साथियों ने सत्ता पर अपनी नाजायज पकड़ बनाए रखने के लिए वेनेजुएला की चुनावी प्रणाली में हेरफेर किया है.

CM मोहन यादव ने वापस दिलाई पुलिस की वर्दी

इंटरनेशनल क्रिकेटर के पिता हो गए थे सस्पेंड
राष्ट्रबाण
भोपाल. मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भारतीय महिला क्रिकेट टीम की प्लेयर क्रांति गौड़ से किया बड़ा वादा निभा दिया है. क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना सिंह की पुलिस की नौकरी को राज्य सरकार ने बहाल कर दिया है. राज्य के खेल एवं युवा कल्याण मंत्री विश्वास सारंग ने सोमवार को इस बात की जानकारी दी है. क्रांति गौड़ मध्य प्रदेश की अंतर-राष्ट्रीय क्रिकेटर हैं और भारतीय महिला क्रिकेट टीम की विश्व कप जीतने वाली महिला क्नडे टीम में शामिल थीं. क्यों सस्पेंड हुए थे क्रांति गौड़ के पिता ?मंत्री विश्वास सारंग की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, क्रिकेटर क्रांति गौड़ के पिता मुन्ना सिंह मध्य प्रदेश पुलिस में आरक्षक के पद पर थे. उन्हें साल 2०११2 में चुनाव ड्यूटी के दौरान लापरवाही के आरोप

'अगर वेनेजुएला में सेना भेजी तो राइफलों से व्हाइट हाउस पर कब्जा कर लेंगे '

जब मादुरो के बेटे ने ट्रंप को दी थी धमकी 'मैं निर्दोष हूं...कोई अपराध नहीं किया. मुझे तीन जनवरी से अगवा करके यहां रखा गया है. मुझे वेनेजुएला में काराकास के मेरे घर से पकड़ा गया था. मैं अब भी अपने देश का राष्ट्रपति हूं..', ये शब्द उस राष्ट्रपति के हैं जिसे रात के अंधेरे में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने उनकी पत्नी सीलिया फ्लोरेस समेत बेडरूम से उठावा लिया. वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी फिलहाल न्यूयॉर्क की एक जेल में कैद हैं. ट्रंप राष्ट्रपति मादुरो को अगवा करने के बाद वेनेजुएला को अपने हिसाब से चलाने की तैयारी में हैं लेकिन एक 'प्रिंस' है जो उनकी इन उम्मीदों पर पानी फेर सकता है. मादुरो को अगवा किए जाने के बाद वेनेजुएला की उप राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज को वहां का अंतरिम राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है. लेकिन ट्रंप चाहते हैं कि वो उनके इशारों

पर काम करें. रोड्रिगेज ने ऐसा कुछ करने से इनकार किया है जिसके बाद ट्रंप ने उन्हें धमकी देते हुए कहा कि अगर वो अमेरिका के कहे अनुसार सत्ता नहीं चलाती तो वेनेजुएला में अमेरिकी सैनिकों की तैनाती की जाएगी. इसी दौरान मादुरो के बेटे ने ट्रंप को धमकी देते हुए कहा थाकि अगर उन्होंने वेनेजुएला की तरफ आंख उठाकर देखा तो उनके सैनिक व्हाइट हाउस पर कब्जा कर लेंगे. ट्रंप की इन धमकियों पर एक 'प्रिंस' बार-बार पलटवार कर रहा है और कह रहा है कि वेनेजुएला सुरक्षित हाथों में है.

इस 'प्रिंस' का नाम है निकोलस मादुरो गुएरा, जो कि मादुरो के बेटे हैं. मादुरो को अगवा किए जाने के बाद से ही उनके बेटे ट्रंप पर हमलावर हैं. उन्होंने ट्रंप की कार्रवाइयों को बाहरी आक्रमण करार देते हुए कहा कि इसके जवाब में राजनीतिक और सैन्य समन्वय की जरूरत है.

काशी एक्सप्रेस में बम की धमकी से हड़कंप

मऊ में पूरी ट्रेन को खाली कराकर पुलिस ने ली तलाशी
राष्ट्रबाण
मऊ. मऊ रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म संख्या एक पर मंगलवार सुबह हड़कंप और अफरा-तफरी का माहौल हो गया. यहां पुलिस कंट्रोल रूम को एक अज्ञात कॉल के द्वारा यह सूचना मिली कि गोरखपुर से मुंबई जा रही काशी एक्सप्रेस ट्रेन में बम रखा है. ट्रेन के मऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंचने के पहले ही मऊ के एसपी सहित भारी पुलिस बल, जीआरपी और आरपीएफ की टीम द्वारा प्लेटफॉर्म पर मौजूद यात्रियों को बाहर निकाल कर पूरे ट्रेन की सघन जांच की गई.



सूचना मिलते ही मऊ पुलिस की पूरी टीम, जीआरपी , आरपीएफ हम सभी लोगों ने तैयारी की हुई थी. जैसे ही ट्रेन मऊ रेलवे स्टेशन पर पहुंची वहां से पब्लिक और यात्रियों को सुरक्षित दूर हटा दिया गया. हम लोगों की संयुक्त टीम द्वारा सभी ट्रेन की बेगियों की चेकिंग की गई . चेकिंग के दौरान अभी ऐसा कुछ नहीं मिला है. हम लोग और भी चेकिंग कर रहे हैं. साथ ही जो अज्ञात कॉल आया था. उसके बारे में भी जानकारी की जा रही है. इलमारी ने कहा कि यह इंटरनेट कॉल लग रहा है. हम लोगों की सर्विलांस टीम इस पर काम कर रही है.

लावारिस बैग दिखाई दिया, जिसे पुलिस ने बड़े डंडे के सहारे प्लेटफॉर्म से बाहर निकाल दिया. फिर बम स्क्वाॅड ने उसकी जांच की लेकिन उसमें भी कुछ नहीं मिला. इस पूरे मामले को लेकर मऊ के

एसपी इलमारी ने बताया कि सुबह 9:30 बजे कंट्रोल रूम को एक अज्ञात कॉल आया था. कॉल करने वाले ने कहा था कि गोरखपुर से मुंबई जाने वाली काशी एक्सप्रेस ट्रेन में बम है.

रविवार को बजट होगा पेश और खुलेगा शेयर बाजार?

सामने आया यह बड़ा अपडेट
राष्ट्रबाण
दिल्ली. केंद्रीय बजट हर साल 1 फरवरी को पेश किया जाता है. इस बार 1 फरवरी रविवार को पड़ रहा है, जिसे लेकर कई तरह की बातें सामने आई हैं. हालांकि अब सरकारी सूत्रों ने मंगलवार को इंडिया टुडे को बताया कि केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रविवार, 1 फरवरी को 2026 का केंद्रीय बजट पेश कर सकती हैं. संसदीय कार्य समिति (CCPA) बुधवार को होने वाली बैठक में बजट सत्र की तारीखों पर आखिरी फैसला ले सकती है. अधिकारियों के अनुसार, CCPA की बैठक में संसद के बजट सत्र का कार्यक्रम और इस साल केंद्रीय बजट पेश करने की सटीक तारीख दोनों तय की जाएंगी, क्योंकि 1 फरवरी को रविवार पड़ने के कारण अनिश्चितता बनी हुई है. सरकारी सूत्रों के मुताबिक, बजट सत्र की शुरुआत 28 जनवरी को संसद के संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के संबोधन से हो सकती है. आर्थिक सर्वेक्षण, 29 जनवरी को पेश किए जाने की संभावना है. 30 और 31 जनवरी को छुट्टियां रहने की संभावना है, जिससे समिति द्वारा मंजूरी मिलने



पहले ही शुरू हो चुकी थी तैयारियां

बजट 2026 की तैयारियों का काम पहले ही शुरू हो चुका है. बजट से पहले की परामर्श बैठकें 9 अक्टूबर, 2025 से नवंबर के मध्य तक आयोजित की गईं. 2026-27 के बजट अनुमान और 2025-26 के संशोधित अनुमानों को अस्थायी रूप से अंतिम रूप दे दिया गया है. वित्त मंत्रालय केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय से जीडीपी अनुमान जुटाने की प्रक्रिया में भी है, जिसका उपयोग बजट से पहले आखिरी गणना में किया जाएगा .

1 फरवरी (रविवार) को केंद्रीय बजट पेश करने कंफर्म हो पाएगा. पिछले साल वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना लगातार आठवां केंद्रीय बजट पेश किया, जिससे उन्होंने वित्त मंत्री के रूप में दो कार्यकाल में पेश किए गए दस बजटों के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई के रिकॉर्ड की बराबरी की.

ओवैसी बोलें- मेरे 6 बच्चे हैं, तुम 8 बच्चे पैदा करो, तुम्हें कौन रोक रहा है?

नवनीत राणा के बयान के बाद ली चुटकी
राष्ट्रबाण
मुंबई. बीजेपी नेता नवनीत राणा के ज्यादा बच्चे पैदा करने वाले बयान के बाद AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने पलटवार किया है और नवनीत का नाम लिए बिना उन पर निशाना साधा है. ओवैसी ने कहा कि उनके छह बच्चे हैं और उन्होंने सवाल किया कि तुम्हें आठ बच्चे पैदा करने से कौन रोक रहा है. महाराष्ट्र के अकोला में बोले ओवैसी महाराष्ट्र के अकोला में एक रैली में ओवैसी ने कहा, मेरे 6 बच्चे हैं और मेरी दाढ़ी सफेद हो रही है. किसी ने कहा कि चार बच्चे होने चाहिए.

मामला जाना चाहता है आजमगढ़

राम रहीम के बाद अबू सलेम ने मांगी इमरजेंसी पैरोल

राष्ट्रबाण
मुंबई. डेरा सच्चा सौदा प्रमुख राम रहीम को बार-बार मिल रही पैरोल को लेकर मचे बवाल के बीच अंडरवर्ल्ड डॉन अबू सलेम ने भी इमरजेंसी पैरोल की मांग करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. राम रहीम रेप और हत्या के मामले में 20 साल की जेल और उपक्रैद की दोहरी सजा काट रहा है. उसे 8 साल में 15वां बार पैरोल मिली है. वहीं अबू सलेम 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट और बिल्डर की हत्या का दोषी है. गैंगस्टर अबू सलेम ने अपने बड़े भाई की मौत के बाद परिवार से मिलने और अंतिम संस्कार की रस्में अदा करने के लिए इमरजेंसी पैरोल की मांग की है. उसने बॉम्बे हाईकोर्ट में याचिका



दायर की है, जिसमें आजमगढ़ (उत्तर प्रदेश) जाने की अनुमति मांगी गई है. सलेम के बड़े भाई अबू हाकिम अंसारी का 14 नवंबर 2025 को निधन हो गया था. सलेम ने उन्हें पिता तुल्य बताया है. अबू सलेम ने अपने बड़े भाई की मौत के बाद इमरजेंसी पैरोल मांगी है, ताकि 40वें दिन की रस्में, कुरान ख्वानी, कब्रिस्तान पर दुआ और परिवार से मिल सके. न्यायमूर्ति ए.एस. गडकरी

अबू सलेम ने 1 दिसंबर को एडीजीपी के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने उसको एस्कॉर्ट पार्टी के साथ जाने की अनुमति दी. लेकिन लाखों रुपये के एस्कॉर्ट खर्च का बोझ सलेम नहीं उठा सका. डीआईजी प्रिजन ने भी उसका आवेदन टुकड़ा दिया. क्योंकि कोई जमानतदार नहीं मिला और सलेम प्लाइट रिकू है. अबू सलेम का

और न्यायमूर्ति श्याम सी. चांडक की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि मुस्लिम रीति-रिवाजों के अनुसार अंतिम संस्कार के बाद 40 दिनों की न्युन हो गया हो चुकी है. इस पर सलेम की ओर से अधिवक्ता फरहाना शाह ने दलील दी कि याचिका समय पर दाखिल की गई थी, लेकिन शीतकालीन अवकाश के कारण उस पर सुनवाई नहीं हो सकी. अबू सलेम ने अपनी याचिका में कहा

कहना है कि उसका छोटा भाई जमान-तदार बनने वाला था, लेकिन वह पदा लिखा नहीं और कुछ गलतफहमी के कारण वह जमानत देने के लिए नहीं आ सका. उसने कहा कि दो वकील उसके जमानतदार बनने को तैयार हैं. उसने अदालत में कहा कि पहले 2009 और 2011 में मां व खाला की मौत पर उसे पैरोल मिली थी और उसने समय पर

है कि उसके बड़े भाई अबू हकीम अंसारी पिछले तीन महीने से गंभीर रूप से बीमार थे. इसलिए उसने जेल अधीक्षक से नियमित पैरोल की प्रक्रिया तेजी से निपटाने का अनुरोध किया था, ताकि वह अपने भाई के जीवित रहते उनसे मिल सके. लेकिन उसका आवेदन लंबित रहा और दुर्भाग्यवश उसके बड़े भाई का उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ इशत पैतुक घर में निधन हो गया. याचिका में सलेम

जेल में आत्मसमर्पण कर दिया था. अबू सलेम 2005 से नासिक सेंट्रल जेल में बंद है. उसे दो मामलों में आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी, पहला मामला 1993 के मुंबई सीरियल ब्लास्ट का था जिसमें 257 लोगों की मौत हुई थी और 1400 लोग घायल हुए थे, और दूसरा मामला 1995 में बिल्डर प्रदीप जैन की हत्या का था.

ने कहा है. 'अपने भाई की मृत्यु के बाद, मैंने कब्रिस्तान में होने वाले मजहबी रस्मों, 40वें दिन की नमाज, कुरान ख्वानी और अन्य मजहबी इबादत में शामिल होने और अपने भाई के परिवार के सभी सदस्यों, विशेषकर महिलाओं और स्वयं के परिवार के सदस्यों को सात्वना देने के लिए जेल अधिकारियों के सामने आपातकालीन प्रतिक्रिया के लिए आवेदन किया था.

भोपाल में 2 हजार से ज्यादा भावी शिक्षकों का प्रदर्शन

मध्यप्रदेश शिक्षक भर्ती में पद बढ़ाने की मांग, डीपीआई का घेराव करने पहुंचे

भोपाल | संवाददाता
rashtabaan.in

मध्यप्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की भारी कमी और शिक्षक चयन परीक्षाओं में बेहद कम पद घोषित किए जाने के खिलाफ मंगलवार को भोपाल में बड़ा आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेशभर से करीब 2000 भावी शिक्षक राजधानी पहुंचे हैं। यह लोक शिक्षण संचालनालय (डीपीआई) और जनजातीय कार्य विभाग का संयुक्त घेराव करने पहुंचे हैं। यहां वे हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। अभ्यर्थियों का आरोप है कि हजारों पद रिक्त होने के बावजूद भर्ती में घोषित सीटें ऊंट के मुंह में जीरा साबित हो रही हैं। इससे न सिर्फ योग्य अभ्यर्थी बाहर हो रहे हैं, बल्कि स्कूलों में पढ़ाई की गुणवत्ता भी प्रभावित हो रही है। प्रदर्शनकारी चेतावनी दे चुके हैं कि यदि सरकार ने उनकी मांगों पर जल्द फैसला नहीं लिया, तो आंदोलन को अनिश्चितकालीन और भूख हड़ताल जैसे चरण में बदला जाएगा। यह प्रदर्शन शिक्षा व्यवस्था में सुधार और युवाओं को न्याय दिलाने की मांग को लेकर किया जा रहा है।



पद बढ़ाने की मांग को लेकर आंदोलन

मध्यप्रदेश स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग द्वारा आयोजित माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा (वर्ग-2) और प्राथमिक शिक्षक चयन परीक्षा (वर्ग-3) में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों का आक्रोश लगातार बढ़ता जा रहा है।

ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग में शून्य पदों का आरोप

अभ्यर्थियों ने जनजातीय कार्य विभाग पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि कई विषयों में ईडब्ल्यूएस और ओबीसी वर्ग के लिए शून्य पद दर्शाए गए हैं, जिससे इन वर्गों के युवाओं में गहरी निराशा है। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि यह सामाजिक न्याय की भावना के खिलाफ है और इससे आरक्षण व्यवस्था पर भी सवाल खड़े होते हैं।

भोपाल में पानी की टंकियां देखने पहुंचे कांग्रेसी, बरखेड़ा पठानी में गंदगी मिली

श्यामला हिल्स के फिल्टर प्लांट का पानी बड़ा तालाब में मिलते दिखा

भोपाल | संवाददाता
rashtabaan.in

इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से 17 लोगों की मौत हो गई। भोपाल में भी कई इलाकों में गंदे पानी की सप्लाई की शिकायतें मिल रही हैं। ऐसे में नगर निगम का अमला मैदान में उतरकर न सिर्फ सैंपल ले रहा है, बल्कि वाल्व भी सुधार रहा है। इसी बीच मंगलवार को कांग्रेसी भी शहर की पेयजल टंकियों और फिल्टर प्लांट की जांच करने निकले। बरखेड़ा पठानी स्थित टंकी में गंदगी मिली तो श्यामला हिल्स के फिल्टर प्लांट का रा वाटर बड़ा तालाब में मिलते दिखा। इस पर कांग्रेसियों ने आपत्ति ली और तुरंत सुधार कराए जाने की चेतावनी दी है।

गंदगी लापरवाही सामने

आई- झूमरवाला

कांग्रेस नेता रविंद्र साहू झूमरवाला ने गोविंदपुरा विधानसभा के बरखेड़ा पठानी क्षेत्र स्थित टंकी पर चढ़कर निरीक्षण किया। वीडियो भी बनाया। इस दौरान टंकी के अंदर और आसपास गंदगी मिली। झूमरवाला ने कहा कि इसी टंकी से रोजाना हजारों लोगों को पीने का पानी सप्लाई होता है। दूषित पानी से संक्रमण और गंभीर बीमारियां फैल सकती हैं। उन्होंने प्रशासन से तत्काल सुधारात्मक कार्रवाई की



पार्श्वों को बड़ा तालाब में पानी मिलते मिला

मंगलवार सुबह नगर निगम के कांग्रेसी पार्श्व श्यामला हिल्स स्थित वाटर फिल्टर प्लांट पहुंचे। नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष शबिस्ता जकी, पार्श्व योगेंद्र सिंह गुड्डू चौहान, मो. जहीर आदि मौजूद थे। नेता प्रतिपक्ष जकी ने बताया कि श्यामला हिल्स के फिल्टर प्लांट का पानी बड़ा तालाब में मिलते दिखा। बड़ा तालाब से ही शहर के कई इलाकों में पानी की सप्लाई की जाती है। ऐसे में रा

वाटर मिलना गलत है। जकी ने कहा कि वाटर ट्रीटमेंट प्लांट चालू नहीं था। सिर्फ कामजी कार्रवाई ही देखने को मिली। रिपोर्ट भी नहीं मिली कि पानी का नियमित सैंपल लिया जाता है। केमिस्ट ग्रेजुएशन पास है। यह रसायन शास्त्र में ग्रेजुएट होना जरूरी है। पानी की गुणवत्ता भी सही नहीं मिली। पानी को फिल्टर करने में जो दिशा-निर्देशों का पानी जरूरी होता है, वह भी नहीं दिखा।

महापौर ने ली बैठक, पानी-सीवेज की समीक्षा की कांग्रेस के विरोध के बीच दोपहर में आईएसबीटी स्थित निगम ऑफिस में महापौर मालती राय ने जल एवं सीवेज को लेकर समीक्षा बैठक भी की। इसमें इंजीनियरों

मांग की। चेतावनी दी कि समय रहते कदम नहीं उठाए गए तो इंदौर जैसी दुखद घटना यहां भी हो सकती है। इसके अलावा टंकी के आसपास गंदगी और शराबियों का जमावड़ा भी दिखाई दिया। झूमरवाला ने बताया कि भोपाल

को जरूरी निर्देश दिए गए। एमआईसी मेंबर रविंद्र यादव, अधीक्षण यंत्री उदित गर्ग, सिविल इंजीनियर आरके त्रिवेदी भी मौजूद थे।

शहर की सभी टंकियों की तुरंत सफाई कराई जाए। यह वक्त चेतावनी देने का नहीं बल्कि तत्काल कार्रवाई का है। पानी जीवन है और जीवन के साथ किसी भी स्तर पर लापरवाही किसी भी कीमत पर स्वीकार्य नहीं हो सकती।

भोपाल | संवाददाता
rashtabaan.in

मध्यप्रदेश की मोहन यादव सरकार के लिए नए साल का पहला मंगलवार कर्ज के बोझ के साथ शुरू हो रहा है। सरकार मंगलवार को बाजार से 4 हजार करोड़ रुपए का नया कर्ज लेने जा रही है। कर्ज की राशि बुधवार को मिलेगी। चालू वित्त वर्ष में 1 अप्रैल से 31 दिसंबर 2025 तक प्रदेश सरकार पहले ही 53100 करोड़ रुपए का कर्ज ले



चुकी है। मंगलवार को लिए जाने वाले नए कर्ज के बाद यह

आंकड़ा बढ़कर 57100 करोड़ रुपए तक पहुंच जाएगा।

भोपाल में युवक ने फांसी लगाकर खुदकुशी की

सुसाइड नोट नहीं मिलने से आत्महत्या के कारणों का खुलासा नहीं

भोपाल | संवाददाता
rashtabaan.in

भोपाल के रातीबड़ थाना क्षेत्र स्थित सेमरी बाजयाफता गांव में रहने वाले युवक ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसके पास से सुसाइड नोट नहीं मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पीएम के लिए रवाना कर दिया है। मामले में मर्ग कायम कर जांच की जा रही है। पुलिस ने बताया कि विनोद अहिरवार पिता रामनारायण (35), सेमरी बाजयाफता में रहता था और किराने के दुकान पर काम करता था। उसके परिवार में पत्नी के अलावा तीन बच्चे हैं। मंगलवार सुबह पत्नी ने उसे फंदे पर लटका



देखा। चीख पुकार सुनकर आसपास के लोग घर पहुंचे और पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने शव बरामद कर पीएम के लिए मचूरी भेज दिया। घटनास्थल का निरीक्षण करने पर सुसाइड नोट नहीं मिला है। साथ ही पत्नी बयान देने की स्थिति में नहीं है। पुलिस का कहना है कि परिजन के बयान दर्ज किए जाएंगे। प्राथमिक जांच में पता चला कि वह शराब पीने का आदी था।

टीटी नगर में भी युवक ने सुसाइड किया

टीटी नगर थाना क्षेत्र स्थित मद्रासी कॉलोनी में एक युवक ने घर में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि रवि जाधव (37) मद्रासी कॉलोनी में रहता था। वह घरों में पुताई करने का काम करता था। पिछले पांच दिन से उसको काम नहीं मिला था। वह शराब पीने का आदी था। उसकी शादी नहीं हुई थी। सोमवार को वह खाना खाकर सो गया था। मंगलवार की सुबह उसके भाई ने उसे फंदे पर लटका देखा। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर मामले की जांच शुरू कर दी है। घटनास्थल से सुसाइड नोट नहीं मिला है।

विदेश जाना था, पासपोर्ट में छिपाई उम्र

भोपाल पासपोर्ट ऑफिस की जांच में खुलासा ; नाबालिग ने किया था आवेदन

भोपाल | संवाददाता
rashtabaan.in

विदेश जाने के लिए एक नाबालिग ने खुद को वयस्क दिखाने के लिए पासपोर्ट आवेदन में ही जन्मतिथि गलत दर्ज कर दी। जब दस्तावेज सत्यापन हुआ तो मामला पकड़ में आ गया। जांच में वास्तविक उम्र 16 वर्ष सामने आने के बाद पासपोर्ट कार्यालय ने आवेदन खारिज करते हुए आवेदक को सख्त चेतावनी दी और फाइल बंद कर दी। जानकारी के अनुसार, पासपोर्ट आवेदन की प्रारंभिक जांच के दौरान अधिकारियों को उम्र को लेकर संदेह हुआ। इसके बाद स्कूल से जुड़े दस्तावेज मांगे गए। रिकॉर्ड मिलान में साफ हुआ कि आवेदन में दर्ज जन्म वर्ष बदला गया था। ताकि, आवेदक वयस्क प्रतीत हो। नाबालिग होने की पुष्टि होते ही पासपोर्ट अदालत ने तत्काल आवेदन निरस्त कर दिया।

पुलिस कार्रवाई से बचने की गुहार

पासपोर्ट ऑफिस के अनुसार, किशोरी ने मामले में पुलिस को

कोर्ट केस छिपाया, फिर लानी पड़ी एनओसी

इसी सुनवाई के दौरान एक अन्य आवेदक का मामला भी सामने आया। जिसने पासपोर्ट आवेदन में अपने खिलाफ अदालत में लंबित प्रकरण की जानकारी नहीं दी थी। पुलिस वेरिफिकेशन में तथ्य उजागर होने पर आवेदन पर एडवर्स रिपोर्ट लगी और नोटिस जारी किया गया। नोटिस के जवाब में आवेदक ने कोर्ट से एनओसी प्राप्त कर पेश की, जिसके बाद आवेदन प्रक्रिया को आगे बढ़ाया गया।

सूचना न देने का आग्रह किया। प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए उसे भविष्य के लिए सचेत किया गया। साथ ही निर्देश दिए गए कि स्कूल मार्कशीट के अनुसार आधार कार्ड में जन्म तिथि का सुधार कराया जाए। अधिकारियों ने यह भी स्पष्ट किया कि नाबालिग आवेदकों के मामले में माता-पिता की उपस्थिति और आवश्यक दस्तावेज अनिवार्य होते हैं। चेतावनी के बाद किशोरी ने गलती स्वीकार की, जिसके बाद फाइल क्लोज कर दी गई।

तीन अलग-अलग अवधि का कर्ज लेगी सरकार

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के माध्यम से सरकार आज तीन हिस्सों में कर्ज लेने जा रही है। इसमें पहले और दूसरे कर्ज की राशि 1500-1500 करोड़ रुपए होगी, जबकि तीसरा कर्ज 1,000 करोड़ रुपए का रहेगा। पहला 1500 करोड़ रुपए का कर्ज 4 साल की अवधि के लिए लिया जाएगा। दूसरा, 1500 करोड़ रुपए का कर्ज 12 साल की अवधि का होगा। तीसरा 1000 करोड़ रुपए का कर्ज 18

साल की लंबी अवधि के लिए लिया जा रहा है। इन सभी कर्ज पर लगने वाले ब्याज का भुगतान सरकार हर साल जुलाई और जनवरी में छमाही आधार पर करेगी। राज्य सरकार की बढ़ती उधारी एक बार फिर वित्तीय प्रबंधन और कर्ज के दबाव को लेकर सवाल खड़े कर रही है, खासकर तब जब चालू वित्त वर्ष में कर्ज का आंकड़ा लगातार बढ़ता जा रहा है।

जापान की तर्ज पर भोपाल में बिना चीरफाड़ होगा पोस्टमार्टम

आधा घंटे में पूरी होगी प्रक्रिया, एम्स में बनेगा वर्चुअल ऑटोप्सी सेंटर ; मिली सैद्धांतिक मंजूरी

भोपाल | संवाददाता
rashtabaan.in

भोपाल जल्द ही देश के उन चुनिंदा शहरों में शामिल हो सकता है, जहां बिना चीरफाड़ के पोस्टमार्टम किया जाएगा। जापान और अन्य विकसित देशों की तर्ज पर एम्स भोपाल में वर्चुअल ऑटोप्सी शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम बढ़ाया गया है। इस मॉडर्न तकनीक से शव का पोस्टमार्टम बिना किसी सर्जिकल कट के संभव होगा। सोमवार को एम्स भोपाल प्रबंधन ने भारत सरकार की स्टैंडिंग फाइनेंस कमिटी की बैठक में इसका औपचारिक प्रस्ताव रखा है। खास बात यह है कि इस प्रस्ताव को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से पहले ही सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी थी। अब इसे वित्त मंत्रालय के प्रतिनिधि मंडल के समक्ष प्रस्तुत किया गया है। सांसद आलोक शर्मा ने कहा कि प्रस्ताव पर रिसर्प्स सकारात्मक रहा है और जल्द ही इसके लिए फंड जारी होने की संभावना है। यह परियोजना मंजूर होती है तो एम्स भोपाल मध्यप्रदेश का पहला ऐसा अस्पताल होगा, जहां वर्चुअल ऑटोप्सी की सुविधा शुरू होगी। शिलॉन स्थित एनईआईजीआरआईएचएमएस द्वारा किए गए अध्ययन में पाया गया कि फांसी के मामलों में वर्चुअल ऑटोप्सी और

डिजिटल एविडेंस होते हैं तैयार

विशेषज्ञों के अनुसार, वर्चुअल ऑटोप्सी से तैयार होने वाली रिपोर्ट डिजिटल साक्ष्य के रूप में बेहद मजबूत होती है। उदाहरण के तौर पर, यदि किसी व्यक्ति की मौत नस में ब्लॉक के कारण हुई है, तो रिपोर्ट में उस नस की 3डी तस्वीर होगी। यह तस्वीर तीन स्तरों में होगी- पहले पूरे शरीर में ब्लॉक की स्थिति, फिर संबंधित अंग और अंत में उस खास नस की क्लोज-अप इमेज। इन डिजिटल साक्ष्यों को लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है और अदालत में भी प्रमाण के तौर पर पेश किया जा सकता है।

परिजनों के आक्रोश का नहीं करना होगा सामना

कई मामलों में परिजन धार्मिक या सामाजिक कारणों से शव की चीरफाड़ नहीं चाहते। इसे लेकर अस्पतालों में विवाद की स्थिति भी बन जाती है। जिसका सामना कई बार मौजूद डॉक्टरों को करना पड़ता है। पुलिस कानूनी प्रक्रिया के तहत पोस्टमार्टम कराती है, लेकिन इससे परिवार मानसिक रूप से आहत होता है। वर्चुअल ऑटोप्सी इस समस्या का समाधान बन सकती है, क्योंकि इसमें शरीर को बिना नुकसान पहुंचाए जांच पूरी की जाती है। इससे परिजनों को शव सीधे अवस्था में सौंपा जा सकेगा।

पारंपरिक ऑटोप्सी के नतीजों में 90 प्रतिशत तक समानता रही।

भोपाल | संवाददाता
rashtabaan.in

प्रदेश के सिविदा कर्मचारियों के एक प्रतिनिधि मंडल ने डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा से मुलाकात कर विभागों में रिक्त पदों पर सिविदा कर्मचारियों, अधिकारियों संविलियन किए जाने और 22 जुलाई 2023 को जारी सिविदा नीति में संशोधन किए जाने की मांग की है। प्रतिनिधिमंडल ने सिविदा कर्मचारियों को वरिष्ठता के हिसाब से विभागों में रिक्त पदों पर नियमित किया जाए अथवा संविलियन किया जाए। सिविदा कर्मचारियों के वेतन भत्ते, वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित किए जाए।



मुलाकात के दौरान डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा को बताया गया कि 22 जुलाई 2023 की सिविदा नीति में 50वें पदों के आरक्षण का उल्लेख किया गया है, जिसमें सिविदा कर्मचारियों को परीक्षा देनी होगी लेकिन चतुर्थ श्रेणी तथा वाहन चालक के जो पद हैं उन पदों पर

मध्य प्रदेश शासन ने भर्ती पर प्रतिबंध लगा रखा हुआ है जिसके कारण चतुर्थ श्रेणी के पदों पर भर्ती नहीं होगी। इस नीति से चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों को कोई लाभ नहीं होगा जिसके कारण 25 से 30 वर्षों से सिविदा पर काम करने वाले कर्मचारी कभी नियमित नहीं हो

पाएंगे। इसलिए स्कूल शिक्षा विभाग और अन्य विभागों में जो सिविदा के पद रिक्त हैं उन रिक्त पदों पर चतुर्थ श्रेणी, वाहन चालक, चौकीदार के सिविदा कर्मचारियों का संविलियन कर दिया जाए। बताया गया कि 22 जुलाई 2023 की सिविदा नीति में अनेक

सिविदा नीति की इन विसंगतियों की जानकारी दी डिप्टी सीएम देवड़ा से प्रतिनिधि मंडल ने कहा कि सिविदा कर्मचारियों को वरिष्ठता के हिसाब से विभागों में रिक्त पदों पर नियमित किया जाए अथवा संविलियन किया जाए। सिविदा कर्मचारियों के वेतन भत्ते, वरिष्ठता के आधार पर निर्धारित किए जाए।

विसंगतियां हैं। इस नीति में संशोधन किया जाए। डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा ने सिविदा कर्मचारियों को आश्वासन दिया कि उनकी समस्याओं को मुख्यमंत्री के संज्ञान में लाकर निर्णय लिया जाएगा। डिप्टी सीएम से मुलाकात करने वालों में म.प्र. सिविदा

समयमान वेतनमान दिया जाए और नियमित कर्मचारियों के समान सभी अवकाश दिए जाए। महिला सिविदा कर्मचारियों को संतान पालन अवकाश दिया जाए। जिन सिविदा कर्मचारियों का ग्रेड पे कम कर दिया है उनका ग्रेड पे सुधारा जाए।

कर्मचारी अधिकारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रमेश राठौर, अल्प वेतन भोगी कर्मचारी संघ समग्र शिक्षा अभियान के संरक्षक भगवान दास ढलिया, अध्यक्ष राजकुमार साकळे के अलावा प्रदेश से आए हुए सिविदा कर्मचारी शामिल रहे।

सं।पा।द।की।र

रेयर अर्थ की दौड़ में दुनिया दांव पर, ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की नई चाल



दुनियाभर में दर्जनों संघर्ष रुकवाने के सैकड़ों दावे कर चुके अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप खुद ही वैश्विक तनाव को भड़का रहे हैं. वेनेजुएला के बाद अमेरिका की ओर से ग्रीनलैंड को लेकर जो मेसेज आया है, वह दुनिया की शांति और स्थिरता के लिए खतरा है. इससे तो अंतरराष्ट्रीय कानून, यूएन चार्टर और देशों की संप्रभुता का कोई मतलब नहीं रह जाएगा.

कड़ी प्रतिक्रिया - ट्रंप प्रशासन में डिप्टी चीफ ऑफ स्टॉफ स्टीफन मिलर की पत्नी केटी मिलर ने एक तस्वीर पोस्ट की. जिसमें ग्रीनलैंड को अमेरिकी झंडे में दिखाया गया है. इसके साथ लिखा था जल्द. स्टीफन को ट्रंप के चहेते लोगों में गिना जाता है, जबकि केटी खुद भी ट्रंप के पहले कार्यकाल में महत्वपूर्ण भूमिकाओं में रह चुकी हैं. ऐसे में उनके ट्वीट पर डेनमार्क और ग्रीनलैंड की तरफ से स्वाभाविक ही कड़ी प्रतिक्रिया आई. कानूनों का उल्लंघन .फिंगडम ऑफ डेनमार्क के तहत आने वाले ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की महत्वकांक्षा पुरानी है. वह कई मौकों पर खुलेआम कह चुके हैं कि उन्हें अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड चाहिए. ऐसे में केटी मिलर की तरफ से आ रहे ऐसे आपत्ति-जनक मेसेज उसी का नतीजा है.

रेयर अर्थ पर नजर . ट्रंप पूरी दुनिया को एक कारोबारी की नजर से देख रहे हैं. उन्हें वेनेजुएला चाहिए, क्योंकि वहां तेल के भंडार हैं और ग्रीनलैंड चाहिए. क्योंकि वहां रेयर अर्थ का खजाना है. यही एक चीज है, जिसने अमेरिका को चीन के साथ ट्रेड वॉर में टिकने नहीं दिया. पिछले साल जब ट्रंप ने टैरिफ बढ़ाया, तो चीन ने जवाब में रेयर अर्थ मिनरल्स की सप्लाई रोक दी थी. थक हारकर अमेरिका को वार्ता की मेज पर आना पड़ा. आज दुनिया की जरूरत का 90% रेयर अर्थ चीन से आता है और अमेरिका की टेक-ऑटो-डिफेंस इंडस्ट्री इसकी मोहताज है. दोस्तों को नुकसान . ट्रंप इसे लेकर चीन का दबदबा कम करना चाहते हैं, लेकिन चोट अपने साथियों को पहुंचा रहे हैं. दूसरी बार सत्ता संभालते ही उन्होंने पड़ोसी कनाडा को अमेरिका का एक राज्य बनाने की इच्छा जाहिर की थी. फिर यूरोप को लेकर नीतियां बदली. जिस डेनमार्क को लेकर उनका स्टॉफ आक्रामकता दिखा रहा है, वह खुद नैटो का सदस्य है और अमेरिका की जिम्मेदारी है उसकी सुरक्षा करना. दांव पर साख . इस तरह के मेसेज केवल बातों तक सीमित नहीं रहते, उनका गहरा कूटनीतिक असर पड़ता है. अमेरिका वह नैतिकता खोता जा रहा है, जिससे रूस को यूक्रेन में और चीन को ताइवान के विलय से रोके.

राशिफल



■ मेष:

इस समय आपके अंदर एक अजीब सी बेचैनी चल रही है. ऐसा लग सकता है कि आप बहुत कुछ करना चाहते हैं, लेकिन चीजें अपनी रफ्तार से नहीं चल रही. कामकाज में दबाव रहेगा, जिम्मेदारियां भी बढ़ेंगी, पर आप उनसे भागने वाले नहीं हैं.

■ वृषभ:

आपके लिए यह समय

थोड़ा सुकून देने वाला है. जो परेशानियां पिछले कुछ समय से चल रही थीं, अब उनमें धीरे-धीरे सुधार नजर आएगा. काम में स्थिरता आएगी और लोग आपकी मेहनत को समझेंगे. मन थोड़ा हल्का रहेगा और परिवार का साथ अच्छा महसूस होगा.

■ मिथुन:

आपका दिमाग इस

समय बहुत तेज चल रहा है. एक साथ कई बातें सोच रहे हैं, कई योजनाएं बना रहे हैं, लेकिन इसी चक्कर में खुद को उलझा भी सकते हैं. बातचीत आपकी सबसे बड़ी ताकत बनेगी, इसलिए मन की बात दबाकर न रखें. काम में नए आइडिया आएंगे, जिनसे फायदा हो सकता है.

साम्राज्यवाद का प्रतिरोध आवश्यक

वेनेजुएला में अमेरिकी हमला यही दर्शाता है कि हम महाशक्तियों की घातक प्रतिस्पर्धा और उनके मनमाने हस्तक्षेपों के दौर में जी रहे हैं. ऐसे दौर में जहां अंतरराष्ट्रीय कानूनों और जंगल के कानूनों में कोई अंतर ही नहीं रह गया है. वेनेजुएला में तख्तापलट के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने शेखी बघारते हुए कहा, ‘हमें इसे फिर से करना होगा, हम फिर से ऐसा कर सकते हैं और कोई हमें रोक नहीं सकता.’ यानी जिसकी लाठी उसी की भैंस. ट्रंप का यह औपनिवेशिक दावा कि ‘हम वेनेजुएला को चलाएंगे और सुनिश्चित करेंगे कि इसे ठीक से चलाया जाए’, स्पष्ट संकेत है कि शक्तिशाली ही शक्तिहीन पर राज करेंगे. ट्रंप ने वेनेजुएला में अवैध रूप से सत्ता परिवर्तन करके वहां के खनिजों को अमेरिकी कंपनियों के एकाधिकार में लाने की खुलेआम घोषणा से सिद्ध कर दिया कि अंतर-राष्ट्रीय कानूनों के जो भी बचे-कुचे बंधन थे, वे भी ध्वस्त होते जा रहे हैं. इससे पहले रूस ने अपने मुकाबले कमजोर पड़ोसी यूक्रेन पर आक्रमण कर उस पर विशेषाधिकारों का दावा किया. रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के अनुसार बड़ी शक्तियाँ को अपने-अपने प्रभाव वाले क्षेत्र रखने की स्वतंत्रता होनी चाहिए और यूक्रेन की संप्रभुता तभी संभव है जब वह रूस के प्रति मित्रवत और



वेनेजुएला में सशस्त्र हमला कर और उसकी आंतरिक राजनीति को जबरदस्ती बदलकर ट्रंप ने हर संभावित हमलावर को सुविधाजनक बहाना दे दिया है. ट्रंप प्रशासन की नवीनतम राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अमेरिका लैटिन अमेरिका पर प्रभुत्व स्थापित करने और एक ऐसे पश्चिमी गोलार्ध का निर्माण करने के लिए उन्नीसवीं सदी के ‘मोनरो सिद्धांत’ को समकालीन संदर्भ में लागू करेगा, जिससे पूरे क्षेत्र की सरकारों को अमेरिका के आर्थिक और सामरिक हितों के अनुसार चलना होगा. अगर लैटिन अमेरिका में अमेरिका की बौंस जायज है, तो एशिया में चीन अपने आप को बेताज बादशाह क्यों न मान ले?

पराधीन रहे. इनके उलट चीन ने अभी तक ताइवान पर पूर्ण पैमाने पर आक्रमण करने या भारत, वियतनाम, फिलीपींस अथवा जापान पर सीधे हमले का प्रयास नहीं किया है, परंतु कमजोर पड़ोसियों के प्रति उसका भी औपनिवेशिक और दबंग रवैया है जो दिन-प्रतिदिन और बिगड़ता जा रहा है. जब सभी बलशाली देश आक्रामक और लुटेरे तेवरों पर उतर आएंगे तो बड़ी मछली का छोटी मछली को निगलना सामान्यीकृत होने लगता है.

जाता है कि वह सिद्धांतों एवं मानदंडों के आधार पर संचालित होती है, लेकिन हालिया उदाहरण कुछ और ही संकेत कर रहे हैं. वेनेजुएला में अमेरिकी हमले के बाद ताइवान को लेकर समय-समय आक्रामकता दिखाते वाले चीन पर भी अंतरराष्ट्रीय कानून वाले तर्क बेमानी हो जाते हैं. लैटिन भाषा में ‘टू कुआकवे’ जैसी एक संकल्पना है, जिसके अनुसार प्रतिद्वंद्वी के व्यक्तिगत व्यवहार और कार्यों को उनके तर्क के साथ असंगत बताकर उनके तर्कों को अमान्य कर दिया जाता है.

उच्च शिक्षा की समस्याओं का समाधान

केवल डिग्री हासिल कर लेने को शिक्षा नहीं कह सकते. शिक्षा वह शक्ति है, जो जीवन को दिशा देती है. सफल शिक्षा एक व्यक्ति के सोचने का तरीका बदल सकती है, उसे जीवन उद्देश्य दे सकती है और अपने भीतर छिपी संभावनाएं पहचानने का अवसर दे सकती है. खासतौर पर उच्च शिक्षा वह पड़ाव है, जहां युवा अपनी रुचियाँ और क्षमताओं को पहचानते हैं और भविष्य की राह प्रशिक्षण की शुरुआत करते हैं . जहां एक तरफ स्कूली शिक्षा हमें हमारे आसपास की दुनिया का ज्ञान देती है, वहीं उच्च शिक्षा छात्रों को अपने विकल्प जानने की आजादी देती है .

उच्च शिक्षा समय है अलग-अलग विषयों और क्षेत्रों को समझने और यह तय करने का कि उन्हें जीवन में क्या करना है. यह प्रक्रिया सरल नहीं, जटिल होती है. एक छात्र के आजादी से अपनी राह चुन सकने के पीछे एक मजबूत संस्थान, संसाधन और निरंतर प्रयास की आवश्यकता होती है. भारत जैसे विशाल और विविध देश में संस्थान निर्माण एक बहुत बड़ी चुनौती है. आज देश की लगभग 65 प्रतिशत आबादी की उम्र 35 वर्ष से कम है. हर साल लाखों छात्र स्कूलों से निकलकर उच्च शिक्षा की ओर रुख करते हैं, लेकिन संस्थानों में इतनी सीटें ही नहीं कि सबको दाखिला मिल सके. नतीजतन प्रतिस्पर्धा और तेज होती जा रही है



और परीक्षाएं और ज्यादा मानकीकृत हो रही हैं. इस सबके साथ-साथ व्यवस्था अक्सर प्रशासनिक सुविधा की सहूलियत देखती है. इस गहन माहौल में हर छात्र की अलग पहचान और क्षमता पर ध्यान दे पाना असंभव हो जाता है. आज भारत में लगभग 70,018 उच्च शिक्षा संस्थान हैं.

भले ही यह उत्साहजनक लगे, लेकिन देश की जरूरतों के मुकाबले अभी भी पर्याप्त नहीं. युवावर्ग अब भी बड़ी संख्या में गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा खोज रहा है. आपूर्ति की कमी का असर छात्र के इस निर्णय पर पड़ता है कि वह कहां पढ़े. सख्त आव्रजन नीतियों के बाद भी भारतीय

छात्र बड़ी संख्या में विदेश पढ़ने जा रहे हैं. कनाडा, अमेरिका और ब्रिटेन उनके प्रमुख गंतव्य हैं. हालांकि अब फ्रांस, आयरलैंड और इटली भी तेजी से छात्रों में लोकप्रिय हो रहे हैं. जनवरी 2025 तक के आंकड़ों के अनुसार 12 लाख से अधिक भारतीय छात्र विदेश में पढ़ रहे थे. इस आंकड़े से घरेलू स्तर पर आवश्यकता और सीमित विकल्प साफ उजागर होते हैं. इन चुनौतियों के बीच से ही बड़े अवसर भी उत्पन्न होते हैं. तेजी से बदलती दुनिया में पहला अवसर नवाचार में निहित है. भारत में हमें अधिक बहुविषयक कार्यक्रमों की आवश्यकता है. हमें ऐसे कार्यक्रमों के बारे में सोचना होगा, जो तकनीक, पर्यावरण, सूचना और रचनात्मक क्षेत्रों से जुड़े हों. मैनेजमेंट, कानून और मेडिकल जैसे

पारंपरिक कोर्स को भी नए ढंग से देखना होगा. नए पाठ्यक्रम, बेहतर तकनीक और उद्योग से पढ़ाई को जोड़ कर भारतीय संस्थान खुद को वैश्विक स्तर पर मजबूत बना सकते हैं. दूसरा बड़ा अवसर है, डिजिटल शिक्षा. हाइब्रिड माडल प्रभावी हो सकते हैं, जिन्हें आनलाइन और आफलाइन पढ़ाई को मिलाकर बनाया गया हो. अगर सही ढंग से लागू किए जाएं तो ये बड़े पैमाने पर लाभकारी शिक्षा का साधन बन सकते हैं. भारत जैसे विशाल और विविध देश में, जहां छात्र दूरदराज के इलाकों में रहते हैं, डिजिटल शिक्षा एक असरदार समाधान प्रस्तुत करती है. अपने सशक्त डिजिटल ढांचे की सहायता से भारत विश्व के लिए एक उदाहरण स्थापित कर सकता है, और उसे ऐसा करना भी चाहिए.

“भारत और बांग्लादेश: अगली परीक्षा”

हमारी नीति बांग्लादेश केंद्रित होगी. हम दिल्ली और रावलपिंडी केंद्रित नहीं होंगे’ - खालिदा जिया के बेटे तारिक रहमान का यह बयान बेहद प्रभावशाली है. बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री बेगम खालिदा जिया का निधन न केवल उस देश के इतिहास में, बल्कि भारत-बांग्लादेश संबंधों के इतिहास में भी एक महत्वपूर्ण घटना है. बेगम खालिदा बांग्लादेश की पहली महिला प्रधानमंत्री थीं. उनकी पार्टी, बांग्लादेश राष्ट्रवादी पार्टी, डेढ़ दशक बाद एक बार फिर सत्ता के करीब पहुंची. कुछ हद तक उनकी अपनी उपलब्धियों के कारण. शेख हसीना, जो इस डेढ़ दशक में उनकी मुख्य राजनीतिक प्रतिद्वंद्वी थीं, फिलहाल भारत में छिपी हुई हैं. उनकी पार्टी, अवामी लीग को वहां की अंतरिम सरकार ने फरवरी में होने वाले आम चुनावों में भाग लेने की अनुमति नहीं दी. इसलिए, इस लगभग नेतृत्वहीन पार्टी का भविष्य अनिश्चित सा लगता है. बांग्लादेशी दो दशकों से अधिक समय से इन दोनों के बीच ‘बेगमों की लड़ाई’ के आदी हो चुके थे. महत्वपूर्ण बात यह है कि इस दौरान बांग्लादेश में लोकतांत्रिक व्यवस्था लगातार लागू रही. यह पूरी तरह से दोषमुक्त नहीं था. हालांकि, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दोनों



पाकिस्तानों में से ‘इस’ पाकिस्तान ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को लागू करने में अधिक परिपक्वता दिखाई है. लेकिन, दोनों बेगमों की अनुपस्थिति में वहां पैदा हुआ राजनीतिक और संस्थागत शून्य अभी भी अंधकार में डूबा हुआ है. इस शून्य का फायदा उठाते हुए, कई वर्षों से निष्क्रिय पड़े इस्लामी चरमपंथी वहां सक्रिय हो गए हैं. उन्हें निश्चित रूप से पाकिस्तान का समर्थन प्राप्त है. और वर्तमान में, बांग्लादेश में भारत-विरोधी लहर चल रही है, जो कुछ हद तक भारत-विरोधी भी है. अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक विश्लेषकों के लिए यह कहना

आवश्यक नहीं है कि यह स्थिति भारत के दो मुख्य शत्रुओं के लिए पहले से कहीं अधिक अनुकूल है. सवाल यह है कि अब हम क्या करेंगे ? विदेश मंत्री एस. जयशंकर खालिदा जिया के अंतिम संस्कार के लिए ढाका गए थे. खालिदा जब मृत्युशय्या पर थीं, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनके स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली थी. इसे बांग्लादेश की नई राजनीतिक वास्तविकता के अनुकूल ढलने की दिशा में एक शुरुआत कहा जा सकता है. यह एक सतर्क स्वागत है. खालिदा जिया की बीएनपी और शेख हसीना की अवामी लीग, दोनों दलों की विचारधारा में कुछ अंतर है.

न्याय के कठघरे में ‘सरकारी उदारता’

आमतौर पर गहन्य अपराधों के दोषी ठहराए गए कैदियों के प्रति गैरजरूरी और एक सीमा से ज्यादा नरमी बरतना न्याय की अवधारणा के अनुकूल नहीं माना जाता है. मगर हत्या और बलात्कार के अपराध में दोषी ठहराए जाने के बावजूद किसी खास सजायाफता कैदी के प्रति सरकार का रुख जरूरत से ज्यादा उदार दिखने लगे, तो स्वाभाविक ही यह सवाल उठता है कि आखिर कानून और सजा का मतलब क्या रह गया ! गौरतलब है कि बलात्कार और हत्या जैसे गहन्य अपराध में दोषी साबित होने के बाद जेल में सजा काट रहे डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख राम रहीम को एक बार फिर चालीस दिनों की पैरोल मिल गई. भले ही इस छूट के लिए सरकार की ओर से पेश दलीलों पर तमाम सवाल उठ रहे हों, लेकिन राम रहीम अगले चालीस दिनों तक जेल के बाहर रहेगा. दरअसल, अदालत में इस पैरोल मिलने के मसले पर हरियाणा सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि वह कोई ‘पेशेवर अपराधी’ नहीं है और जेल में ‘ अच्छे चाल-चलन’ वाला कैदी है. सवाल है कि जिस कसौटी पर सरकार ने राम रहीम के प्रति लगातार उदारता दिखाई है, क्या वह यही पैमाना जेल में बंद गहन्य अपराधों के अन्य दोषियों के प्रति भी लागू करती है. दो डेरा साध्वियों से बलात्कार के मामले के अलावा राम रहीम को हत्या के अन्य मामले में भी दोषी ठहराया जा चुका है. मगर सजा काटने के लिए जेल में जाने से लेकर अब तक उसे पंद्रहवीं बार ‘पैरोल’ या फिर ‘फरलो’ पर बाहर आने की सुविधा मुहैया कराई गई है. अब तक वह कुल चार सौ दिन से ज्यादा वक्त तक जेल से बाहर रह चुका है.



गहन्य अपराधों के दोषियों को लेकर कोई सरकार शायद ही कभी इस हद तक उदार होती है. सही है कि पैरोल एक कानूनी व्यवस्था है और इसके तहत कैदी को शर्तों के साथ जेल से कुछ दिनों के लिए रिहा किया जाता है, लेकिन इस कानूनी प्रावधान का बेजा इस्तेमाल न्याय की अवधारणा पर चोट पहुंचाने से अलग नहीं है. सरकार को इस बात से शायद कोई फर्क नहीं पड़ता कि इससे कानूनों की मनमानी व्याख्या और पीड़ितों के प्रति न्याय की अवधारणा को चोट पहुंचाने को लेकर कैसे उदाहरण बन रहे हैं !

अलग है और यही बात इस समय आपको आगे ले जा सकती है . नए विचार, नए रास्ते और अलग नजरिया लोगों को प्रभावित करेगा . काम में इन्वोवेशन से फायदा हो सकता है . पैसों में सुधार के संकेत हैं, लेकिन जोखिम सोच-समझकर लें . धनुः आप इस समय संतुलन की तलाश में हैं . दिल कुछ और चाहता है और दिमाग कुछ और कहता है . फैसले लेने में थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन धराराने की जरूरत नहीं है . कामकाज में साझेदारी या दूसरों की राय अहम रहेगी . पैसों में स्थिरता रहेगी, लेकिन बड़े फैसले फिलहाल टालना बेहतर होगा . मकरः आप अंदर ही अंदर बहुत कुछ महसूस कर रहे हैं . बाहर से भले

शांत दिखें, लेकिन मन में कई सवाल चल रहे हैं . यह समय खुद को समझने और पुराने धावों से बाहर आने का है . काम में बदलाव या नई जिम्मेदारी मिल सकती है . कुंभः आप आगे बढ़ने की सोच में हैं . कुछ नया सीखने, कहीं जाने या अपनी सोच को फैलाने का मन करेगा . काम में नई दिशा मिल सकती है, जिससे उत्साह बढ़ेगा . पैसों का खर्च यात्रा, पढ़ाई या किसी योजना पर हो सकता है . मीनः आपका दिल इस समय बहुत कोमल है . आप दूसरों के लिए ज्यादा सोचते हैं, लेकिन खुद की जरूरतों पीछे रह जाती है . कामकाज में मन लगेगा, लेकिन ध्यान भटक भी सकता है . पैसों में खर्च बढ़ सकता है .

निर्यात को गति देने के लिए ‘मार्केट एक्सेस सपोर्ट’ काफी नहीं

केंद्र सरकार ने 4,531 करोड़ रुपये की जो बाजार पहुंच सहयोग (मार्केट एक्सेस सपोर्ट) योजना घोषित की है, वह एक स्वागत योग्य कदम है. खासतौर पर इसलिए क्योंकि यह ऐसे समय पर आई है जब निर्यातकों को धीमी होती वैश्विक मांग के साथ प्रमुख बाजारों मसलन अमेरिका आदि में उथल-पुथल का सामना करना पड़ रहा है. खरीदार-विक्रेता मुलाकात, व्यापार मेलों, खरीदार प्रतिनिधिमंडलों का उल्टा दौरा और बाजार विविधीकरण आदि यह समझ सामने लाते हैं कि कंपनियों की मदद करके हम नए बाजार तलाश सकते हैं, अपनी मौजूदगी प्रदर्शित कर सकते हैं और जरूरत पड़ने पर शुल्क वृद्धि से त्रस्त क्षेत्रों से परे पहुंच बना सकते हैं. यह योजना सूक्ष्म, लघु और मझोले उपक्रमों यानी एमएसएमई की ओर खासतौर पर झुकाव रखती है. बहरहाल, एंकिजम बैंक की एक रिपोर्ट दिखाती है कि उद्यम पोर्टल पर पंजीकृत एमएसएमई में से केवल एक फीसदी ही निर्यात कर रहे हैं. विदेश में मौजूद अवसरों के बारे में जानकारी की कमी, खरीदारों के साथ कमजोर रिश्ता, मार्केटिंग की चुनौतियां और ऋण की कमी आदि बाधा बने हुए हैं. इस संदर्भ में, समर्थित आयोजनों में एमएसएमई की न्यूनतम 35 फीसदी अनिवार्य भागीदारी प्रवेश बाधाओं को कम करती है और निर्यात प्रोत्साहन में लंबे समय से चले आ रहे उस असंतुलन को दूर करती है, जिसने बड़े उद्यमों को प्राथमिकता दी है.



‘दूषित’ शासन के शिकार



आजकल महाराष्ट्र में नगरपालिका चुनाव पूरे जोर-शोर से चल रहे हैं. सत्ताधारी भाजपा रंग-बिरंगे वादों के गुब्बारे आसमान में उड़ा रही है. लेकिन इंदौर और गुजरात के गांधीनगर में हुई भयानक घटनाओं ने इन गुब्बारों की हवा निकालकर रख दी है. इंदौर में दूषित पानी का कहर पिछले छह-सात दिनों से थमने का नाम नहीं ले रहा है. इसी बीच गुजरात के गांधीनगर में भी यह बात सामने आई है कि दूषित पानी के कारण सौ से अधिक बच्चे बीमार पड़ गए हैं. हालांकि, सौभाग्य से गांधीनगर में किसी की जान नहीं गई है, लेकिन इंदौर में दूषित पानी से मरने वालों की संख्या बढ़कर १७ हो गई है. इन दोनों राज्यों और नगरपालिकाओं में भाजपा ही सत्ता में है. गुजरात तो प्रधानमंत्री मोदी और गुज मंत्री अमित शाह का गृह राज्य भी है. भाजपाई और अंधभक्त वर्षों से मोदी के ‘गुजरात मॉडल’ का ढोल पीटते आ रहे हैं. यही मंडली इंदौर शहर के विकास प्रबंधन का ढोल भी पीटती रहती है.

इराक से पनामा और अब वेनेजुएला

वेनेजुएला पर अमेरिका की कार्रवाई के मुद्दे पर भी भारत ने बातचीत से मसले को सुलझाने और क्षेत्र में शांति एवं स्थिरता कायम रखने पर जोर दिया है.



मैं तेजी से बदल रही स्थिति पर करीबी नजर भी रखी जा रही है, ताकि आने वाले समय में राष्ट्रहित की रक्षा के लिए उचित कदम उठाए जा सकें. भारत सहित कई देशों ने इस घटनाक्रम पर गहरी चिंता जताई है और वेनेजुएला की संप्रभुता एवं वहां के लोगों की सुरक्षा की वकालत की है. इस बीच, यह सवाल भी उठ रहा है कि किसी राष्ट्र पर हमला कर वहां के प्रमुख और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर देश से बाहर ले जाने की अमेरिका की कार्रवाई क्या अंतरराष्ट्रीय नियम-कानूनों का उल्लंघन नहीं है ? गौरतलब है कि अमेरिका ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर मादक पदार्थों की तस्करी में शामिल होने का लगातार आरोप लगाने के बाद शुक्रवार देर रात राश्यानी काराकस पर हमला कर दिया था. इस दौरान मादुरो और उनकी पत्नी को हिरासत में लेकर न्यूयॉर्क ले जाया गया. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि मादुरो के खिलाफ न्यूयॉर्क में मुकदमा चलाया जाएगा. यह कोई पहली बार नहीं है कि अमेरिका ने किसी देश में सत्ता परिवर्तन का प्रयास किया है. वर्ष 1965 में अमेरिका ने डोमिनिकन गणराज्य में बड़ी संख्या में अपने सैनिक भेजे, ताकि 1963 में तख्तापलट के तहत हटाए गए पूर्व राष्ट्रपति जुआन बोश की वापसी को रोका जा सके. वर्ष 1989 में अमेरिकी सैनिकों ने पनामा पर धावा बोला, जिसका मकसद तत्कालीन जनरल मैनुअल नोरिएगा को हटाना था, जिन पर मादुरो की तरह ही मादक पदार्थों की तस्करी के आरोप थे. वर्ष 2003 में अमेरिका के नेतृत्व में इराक पर हमला कर सद्दाम हुसैन के लंबे शासन का अंत कर दिया गया. इसी तरह वर्ष 2004 में हैती के तत्कालीन राष्ट्रपति को सत्ता से हटकर अफ्रीका भेज दिया गया. यह बात सही है कि अगर दुनिया के किसी हिस्से में मानव सुरक्षा का गंभीर संकट हो, तो किसी दूसरे देश के हस्तक्षेप को तभी उचित ठहराया जा सकता है.

जनसुनवाई में कलेक्टर ने सुनी आवेदकों की समस्या

 बालाघाट | डेस्क
rashtrabaan.in

प्रत्येक मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई की कड़ी में 06 जनवरी को कलेबे ट्रेट सभाकक्ष में जनसुनवाई का आयोजन किया गया। कलेबे टर श्री मृणाल मीना की अंघे यक्षता में जिला पंचायत सीईओ श्री अभिषेक सराफ, अपर कलेबे टर श्री डीपी बर्मन, संयुबे त कलेबे टर श्री राहुल नायक, डिटी कलेक्टर श्री प्रदीप कौरव ने आवेदकों की समरे याओं को सुना और संबंधित विभागों के अधिकारियों को उनका निराकरण करने के निर्देश दिये। जनसुनवाई में 61 आवेदक अपनी समस्या लेकर आए थे।



जनसुनवाई में लांजी तहसील की मानसी पटले नियमानुसार अतिथि शिक्षक के पद पर नियुक्ति दिलाने की मांग लेकर आयी थी। मानसी पटले का कहना था कि शिक्षा विभाग द्वारा जारी मेरिट सूची में उसका चयन अतिथि शिक्षिका

61 आवेदकों ने दिये अपनी समस्याओं से संबंधित आवेदन

(प्री-प्राइमरी) पद के लिए क्रमांक 01 पर हुआ था। किंतु चयन के बावजूद विद्यालय प्राचार्य द्वारा प्रशासनिक स्तर पर हुई छुटि के कारण उन्हें प्री-प्राइमरी के स्थान पर प्राइमरी कक्षाओं में जॉइन करा दिया गया। मानसी ने बताया कि वह बीते

चार माह से निरंतर पूर्ण निष्ठा एवं ईमानदारी से प्राथमिक शाला सुलसुली में शिक्षण कार्य कर रही है, किंतु अब विद्यालय के प्रभारी प्राचार्य द्वारा उनसे विद्यालय आने के लिए मना किया जा रहा है, साथ ही अभद्रता पूर्ण व्यवहार किया जा रहा है। इस प्रकरण में जिला शिक्षा अधिकारी को शीघ्र कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। किरनापुर तहसील के ग्राम बेनेगांव की निवासी सलिता गुरबेले लाइली बहना योजना से उसका नाम काटने संबंधी शिकायत लेकर आयी थी। सलिता का कहना था कि 25 अप्रैल 2025 से उसे लाइली बहना

योजना की राशि मिलना बंद हो गई है। सलिता ने बताया कि इस संबंध में उसने सीएम हेल्पलाइन में शिकायत दर्ज कराई गई थी किंतु उसमें बताया जा रहा है कि आपके द्वारा स्वयं योजना का त्याग किया गया है, जबकि योजना का त्याग करने संबंधी कोई कार्यवाही सलिता द्वारा नहीं की गई है। इस प्रकरण में महिला एवं बाल विकास अधिकारी को आवश्यक कार्यवाही करने कहा गया है। वारासिवनी तहसील के अंतर्गत ग्राम पंचायत पदमपुर के मेखराम ठकुरेले अपनी माता का राशन कार्ड से नाम काट देने संबंधी शिकायत लेकर आये

थे। मेखराम ने बताया कि उसकी माता जीवित हैं, इसके बावजूद पंचायत द्वारा उनका नाम राशन कार्ड से हटा दिया गया है। शिकायत में यह भी बताया गया कि पंचायत क्षेत्र में समान नाम की एक अन्य महिला की मृत्यु होने के बावजूद उसका नाम योजनाओं में दर्ज है और लाभ उसके परिवार को मिल रहा है। पीड़ित परिवार ने कलाबाई ठकुरेले का नाम पुनः राशन कार्ड में जोड़ने, पेंशन चालू कराने तथा दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। इस प्रकरण में उप संचालक सामाजिक न्याय को आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। जनसुनवाई में लांजी

तहसील के ग्राम मनरी के ग्रामीण सिंचाई संबंधी समस्या लेकर आये थे। ग्रामीणों ने रबी फसल की सिंचाई के लिए नहर से पर्याप्त पानी दिलाने की मांग की। इस प्रकरण में जल संसाधन विभाग के कार्यपालन यंत्री को आवश्यक कार्यवाही करने के निर्देश दिए गए हैं। जनसुनवाई में ग्राम खामघाट की निवासी तामेश्वरी बिसेन अपने पति की दुर्घटना में मृत्यु होने पर शासन से मिलने वाली सहायता राशि दिलाने की मांग लेकर आयी थीं। तामेश्वरी का कहना था की उसका दूसरा विवाह अशोक बिसेन से हुआ था और तब से लेकर वह अशोक बिसेन के साथ दाम्पत्य जीवन का निर्वहन कर रही है। 03 सितम्बर 2025 कां उसके

पति की कुएँ में गैस रिसाव होने के कारण मृत्यु हो गयी है। तामेश्वरी ने बताया कि पति के मृत्यु प्रमाण पत्र पर उसके नाम के स्थान पर पहली पत्नि रीता बिसेन का नाम दर्ज किया गया है। उसके पति ने उसके नाम से कृषि यन्त्र, ट्रैक्टर, पिकअप, मोटर साइकिल के लिए ऋण लिया था जिसकी वसूली के लिए बैंक व फाइनेंस कंपनी तामेश्वरी वरी को परेशानी कर रही है जबकि पति की मृत्यु के पश्चात मिलने वाली सहायता राशि तामेश्वरी के पति की पहली पत्ने नी को मिल रही है। कलेक्टर ने एसडीएम वारासिवनी को तामेश्वरी के प्रकरण पर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।

सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की कलेक्टर ने समक्ष में की सुनवाई

नगर पालिका बालाघाट के सीएमओ एवं उपयंत्रियों का 02 दिन का वेतन काटने के निर्देश

 बालाघाट | डेस्क
rashtrabaan.in

कलेक्टर श्री मृणाल मीना प्रत्येक मंगलवार को सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों का रण्डमली चयन कर संबंधित विभाग के अधिकारी एवं शिकायतकर्ता का समक्ष में बुलवाकर शिकायत को सुना जाता है और उस पर आवरे यक कार्यवाही के निर्देश दिये जाते हैं। शिकायत के निराकरण में लापरवाही पाये जाने पर संबंधित पर कार्यवाही के निर्देश भी दिये जाते हैं। इसी कड़ी में 06 जनवरी को कलेक्टर द्वारा 18 शिकायतों की समक्ष में सुनवाई की गई है।

कलेक्टर श्री मीना ने ग्राम किरनापुर के शिकायतकर्ता कोमलदास मेश्राम द्वारा की गई बटांकन नहीं किये जाने संबंधी शिकायत के निराकरण के संबंध में पटवारी एवं राजस्व निरीक्षक से जानकारी ली। इस दौरान बताया गया कि इस शिकायत में नबे शा बटांकन के संबंध में आदेश पारित किया जा चुका है। इसी प्रकार किरनापुर तहसील के अंतर्गत ग्राम



खपराझरी के शिकायतकर्ता सतीष परते द्वारा अपनी भूमि पर किये गए अतिक्रमण संबंधी शिकायत को सुना गया, जिस पर पटवारी द्वारा बताया गया कि सतीष द्वारा जिस भूमि पर अतिक्रमण किये जाने की शिकायत की गई है उस पर उसका नाम दर्ज नहीं है और उसे इस संबंध में बता दिया गया है। शिकायतकर्ता सतीष अब संतुष्ट है और उसने अपनी शिकायत वापस ले ली है।

कलेक्टर द्वारा समक्ष में की गई सुनवाई के दौरान वारासिवनी तहसील के ग्राम वारा निवासी रामप्यारे आसरे की अतिक्रमण संबंधी शिकायत को संतुष्टि पूर्वक

बंद कराया गया। कटंगी तहसील के अंतर्गत अर्जुनाला निवासी अभिषेक गुे ता द्वारा शिकायत की गई थी कि इंद्रुबाई द्वारा उसके घर के सामने स्थित त शासकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है और उस पर झोपड़ी बनाकर रहती है। जबकि उसके बच्चे चें एवं परिजन सभे पे न है और शासकीय सेवा में है। इस प्रकरण में हाईकोर्ट द्वारा भी कहा गया है कि यदि सरकारी भूमि पर अतिक्रमण है तो उसे हटाय जा सकता है। इस प्रकरण में कलेबे टर श्री मीना ने कटंगी तहसीलदार को शासकीय भूमि पर किये गए अतिक्रमण को हटाने के

निर्देश दिये हैं। इस पर शिकायतकर्ता द्वारा अपनी शिकायत वापस ली गई है। सीएम हेले पलाइन की लंबित शिकायतों की समक्ष में सुनवाई के दौरान खैरलांजी तहसील के ग्राम सावरी के उमाशंकर लिले हारे, वारासिवनी के डिलेश गौतम, परसवाड़ा तहसील के ग्राम समनापुर की चंपाबाई की शिकायतों का समाधान होने पर उं हें बंद कराया गया है। नगरीय क्षेत्र बालाघाट की सीएम हेले पलाइन की लंबित शिकायतों की सुनवाई के दौरान पाया गया कि मुखे य नगर पालिका अधिकारी श्री

बीडी कतरोलिया, उपयंत्री े योति एवं प्रीति द्वारा जल प्रदाय एवं अतिक्रमण संबंधी शिकायतों का उचित निराकरण दर्ज नहीं किया जा रहा है और भौतिक रूप से भी उन पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है। जिस पर कलेबे टर श्री मीना ने इन तीनों अधिकारियों का 02 दिन का वेतन काटने के निर्देश दिये हैं। इस दौरान शिकायतकर्ता प्रशांत चौरसिया, आदर्श नेवारे, मोहित नागरे वर की जल प्रदाय संबंधी शिकायतों, अनिल शर्मा की अतिक्रमण हटाने संबंधी एवं निलाजी चौहान की नालियों के पानी की निकासी े यवरे था संबंधी शिकायतों का बंद कराया गया। इसके साथ ही नगर पालिका के अधिकारियों को सखे त निर्देश दिये गए कि अवैध नल कनेबे शन काटे जाए और शासकीय भूमि पर अतिक्रमण संबंधी शिकायतों पर ते काल कार्यवाही की जाए। वार्ड नं. 32 नर्मदा नगर के आर्दे य सिंह, वार्ड नं. 10 भटेरा चौकी के अनिल कुमार पटले की नल से पानी नहीं आने संबंधी शिकायतों का े वरित निराकरण करने के निर्देश दिये गए।



 बालाघाट | डेस्क
rashtrabaan.in

कृषि कार्य एवं दुग्ध उत्पादन में उन्नत नस्ल के स्वास्थ्य पशुओं की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इन्ही तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए पशु चिकित्सा विभाग द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में शिविर लगाकर किसानों एवं पशुपालकों के बीमार पशुओं का उपचार किया जा रहा है। इसी कड़ी में 06 जनवरी 2026 को बालाघाट विकासखंड के ग्राम रोशना में पशुपालन विभाग के तत्वावधान में पशु चिकित्सा एवं स्वास्थ्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर का उद्देश्य ग्रामीण पशुपालकों को उनके पशुओं के लिए सुलभ एवं निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना रहा। उप संचालक पशु

चिकित्सा सेवायें डॉ एन डी पुरी के मार्गदर्शन में आयोजित इस शिविर के दौरान गाय, भैंस, बकरी सहित अन्य घरेलू पशुओं का निःशुल्क स्वास्थ्य परीक्षण किया गया। बीमार पशुओं का उपचार कर आवश्यक औषधियों का निःशुल्क वितरण किया गया। साथ ही पशुओं को कुमिनाशक दवा पिलाई गई, टीकाकरण किया गया एवं बाह्य परजीवी नियंत्रण हेतु के लिए उपचार भी प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त पशुपालकों को पशु पोषण, स्वच्छता, रोग निवारण एवं बेहतर पशु प्रबंधन के संबंध में उपयोगी परामर्श दिया गया। शिविर में पशु चिकित्सक डॉ. बादल पटले एवं सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी श्रेया बांगरे द्वारा पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण कर बीमार पशुओं का

उपचार किया गया। इसमें पैरावैट स्टाफ शिवम ठाकरे एवं जयनारायण आंडे, गौसेवक झाड़ूलाल शरणगात, मैत्री शुभम लिलहारे ने महत्वपूर्ण योगदान दिया। इस अवसर पर पंचायत प्रतिनिधि विनोद हरिनखेडे भी उपस्थित रहे और सभी के सहयोग से शिविर सुव्यवस्थित एवं सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। शिविर के दौरान ग्राम रोशना के लगभग 34 पशुपालकों के 150 से अधिक पशुओं का स्वास्थ्य परीक्षण एवं उपचार किया गया। पशुपालकों ने इस पहल की सराहना करते हुए कहा कि ऐसे शिविरों से उनके समय और धन दोनों की बचत होती है। उन्होंने भविष्य में भी इसी प्रकार के पशु स्वास्थ्य शिविर आयोजित करने की आवश्यकता बतायी।

एसडीएम एवं तहसीलदारों द्वारा अलग-अलग ग्रामों में की गई जनसुनवाई

 बालाघाट | डेस्क
rashtrabaan.in

कलेक्टर श्री मृणाल मीना के निर्देश पर पेटे येक मंगलवार को सभी एसडीएम एवं तहसीलदार द्वारा अपने क्षेत्र के अलग अलग ग्रामों में जाकर जनसुनवाई की जा रही है और ग्रामीणों की समरे याओं का सुना जा रहा है।

06 जनवरी को वारासिवनी एसडीएम श्री कार्तिकेय जायसवाल ग्राम पंचायत लिंगमारा, बैहर एसडीएम श्री अर्पित गुे ता ग्राम गोगाटोला, परसवाड़ा एसडीएम श्री श्रीश े यासी ग्राम लौगूर, लांजी एसडीएम श्री कमल सिंहसार ग्राम रिसेवाड़ा एवं किरनापुर एसडीएम श्री एमआर कोल ग्राम पंचायत बिनोरा में आयोजित जनसुनवाई में शामिल हुए। इसी प्रकार जनपद पंचायत बालाघाट के मुखे य कार्यपालन अधिकारी ममता कुलरे ते एवं तहसीलदार मंजुला मोहबिया ग्राम पंचायत रझ, खैरलांजी तहसीलदार छवि पंत ग्राम पंचायत सालेटेका एवं बिरसा तहसीलदार ग्राम झामुल एवं

तिरोड़ी तहसीलदार श्री शांडिले य ग्राम कोडबी में आयोजित जनसुनवाई में शामिल हुए।

लिंगमारा मे आयोजित जनसुनवाई में 24 आवेदन प्राप्े त हुए जबकि सालेटेका में आयोजित जनसुनवाई में 28 आवेदन प्राप्े त हुए। वारासिवनी एसडीएम श्री जायसवाल ने ग्राम लिंगमारा में जनसुनवाई के पश्चात शासकीय प्राथमिक शाला का निरीक्षण किया और बच्चे चों के शैक्षणिक रे तर की जांच की। बालाघाट तहसीलदार एवं जनपद सीईओ ने ग्राम रझ में जनसुनवाई के पश्चात प्राथमिक शाला में बच्चों को दिये जा रहे मध्याह्न भोजन का निरीक्षण किया। इसी प्रकार तिरोड़ी तहसीलदार श्री शांडिले य द्वारा ग्राम कोडबी की माधे यमिक शाला में मधे याने ह भोजन का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान पाया गया कि बच्चे चों को मे- यू के अनुसार भोजन दिया जा रहा है। ग्राम लौगूर में आयोजित जनसुनवाई में पेयजल एवं बिजली से संबंधित समस्या ग्रामीणों द्वारा बतायी गई।

एस.एस.पी. महाविद्यालय द्वारा कॉलेज चलो अभियान का सफल आयोजन

 बालाघाट | डेस्क
rashtrabaan.in

शासकीय एसएसपी महाविद्यालय वारासिवनी द्वारा कॉलेज चलो अभियान 2026-27 के प्रथम चरण का प्रभावी संचालन दिनांक 05 दिसंबर 2025 से 05 जनवरी 2026 तक सफलतापूर्वक किया गया। यह अभियान महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. एस.एस. गेडाम के मार्गदर्शन एवं नोडल अधिकारी प्रो. हेमंत

कुमार गनवर के संयोजन में संपन्न हुआ। अभियान के अंतर्गत महाविद्यालय के क्षेत्राधिकार में आने वाले शासकीय एवं अशासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए गए। साथ ही विद्यार्थियों के अभिभावकों एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों से संवाद कर कॉलेज चलो अभियान के उद्देश्यों एवं उच्च शिक्षा के महत्व की विस्तार से जानकारी दी गई। कार्यक्रम

के दौरान विद्यार्थियों एवं अभिभावकों को महाविद्यालय में संचालित ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, विभिन्न स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों, र्राज एवं केंद्र शासन द्वारा संचालित छात्रवृत्ति योजनाओं तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति के नवीन प्रावधानों से अवगत कराया गया। इसके अतिरिक्त महाविद्यालय में उपलब्ध राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) इकाई, एनसीसी, ग्रंथालय, एवं

कैरियर मार्गदर्शन प्रकोष्ठ के माध्यम से विद्यार्थियों को कैरियर विकल्पों, उच्च शिक्षा के अवसरों एवं रोजगार की संभावनाओं की जानकारी प्रदान की गई। इस अभियान के सफल संचालन में महाविद्यालय के समस्त शैक्षणिक स्टाफ का सराहनीय योगदान रहा। महाविद्यालय प्रशासन द्वारा अल्पकों विद्यार्थियों के भविष्य निर्माण की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल बताया गया।

सेवा, अनुशासन, नेतृत्व और सामाजिक चेतना की अनुपम मिसाल बना शिविर

सात दिवसीय विशेष शिविर का उद्देश्यपूर्ण समापन

 बालाघाट | डेस्क
rashtrabaan.in

प्रधानमंत्री कॉलेज ऑफ़ एक्सीलेंस शासकीय जटाशंकर त्रिवेदी स्नातकोत्तर महाविद्यालय, बालाघाट की राष्ट्रीय सेवा योजना (एनएसएस) बालक एवं बालिका इकाई द्वारा ग्राम कुम्हारी स्थित पीएम श्री अनंती बाई शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परिसर में आयोजित सात दिवसीय विशेष शिविर का समापन रविवार, 4 जनवरी 2026 को गरिमावर्ध, भावनात्मक एवं प्रेरणादायी वातावरण में सम्पन्न हुआ। यह शिविर 29 दिसंबर 2025 से 4 जनवरी 2026 तक

सेवा, अनुशासन, सामाजिक उत्तरदायित्व एवं राष्ट्र निर्माण की भावना के साथ संचालित किया गया। समापन समारोह की अध्यक्षता महाविद्यालय के प्राचार्य एवं शिविर संरक्षक डॉ. अशोक कुमार मराठे ने की। विशेष अतिथि के रूप में वरिष्ठ प्राध्यापक डॉ. पी. एस. कातुलकर, जनपद सदस्य श्रीमती लक्ष्मी दशहरे, ग्राम पंचायत कुम्हारी के सरपंच श्री सावन पिछोड़े, उपसरपंच श्रीमती प्रमिला सहित जनप्रतिनिधि, महाविद्यालय के प्राध्यापकगण, एनएसएस स्वयंसेवक-स्वयंसेविकाएँ एवं बड़ी संख्या में ग्रामवासी उपस्थित रहे। शिविर के सात दिनों में स्वयंसेवकों को विभिन्न दलों में विभाजित कर

स्वच्छता अभियान, श्रमदान, प्रभात फेरी, सामाजिक जागरूकता गतिविधियाँ, भोजन एवं रसोई संचालन, मंच सज्जा, सांस्कृतिक कार्यक्रमों का संचालन तथा ःशिविर दर्पण- जैसे रचनात्मक समाचार पत्र के निर्माण की जिम्मेदारियाँ सौंपी गईं। इन सभी गतिविधियों का संचालन स्वयंसेवकों ने पूर्ण अनुशासन, आपसी समन्वय एवं नेतृत्व क्षमता के साथ किया, जिससे शिविर एक जीवंत सामाजिक प्रयोग के रूप में उभरकर सामने आया। समापन दिवस की शुरुआत ग्राम कुम्हारी में अंतिम प्रभात फेरी एवं शिविर स्थल की व्यापक स्वच्छता से हुई। इसके पश्चात समापन समारोह आयोजित किया गया, जिसमें

अतिथियों ने एनएसएस के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि ऐसे शिविर ग्रामीण समाज में स्वच्छता, सामाजिक चेतना, आपसी सहयोग एवं राष्ट्रभक्ति की भावना को सुदृढ़ करते हैं। जनपद सदस्य श्रीमती लक्ष्मी दशहरे ने कहा कि एनएसएस शिविर युवाओं को संवेदनशील नागरिक बनाने हैं और ग्रामीण विकास में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। महाविद्यालय के प्राचार्य डॉ. अशोक कुमार मराठे ने अपने अध्यक्षीय उद्बोधन में कहा कि शिविर के दौरान अर्जित सेवा, अनुशासन एवं नेतृत्व के गुण स्वयंसेवकों के व्यक्तित्व निर्माण में आजीवन सहायक सिद्ध होंगे।

कॉलेज चलो अभियान के तहत लालबर्‍रा महाविद्यालय का ग्राम पंचायतों में संपर्क कार्यक्रम

 बालाघाट | डेस्क
rashtrabaan.in

शासकीय महाविद्यालय लालबर्‍रा द्वारा कॉलेज चलो अभियान के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इसी क्रम में दिनांक 06 जनवरी 2026 को महाविद्यालय के सहायक प्राध्यापकों डॉ. प्रदीप कुमार भिमटे, श्री नितेश कुमार, डॉ. आशीष बागडे, श्री दीपक अहिखार एवं श्री व्यंकटरमन नागपुरे द्वारा ग्राम पंचायत बल्हारपुर एवं ग्राम पंचायत कटंगझरी में बैठक आयोजित कर विद्यार्थियों, अभिभावकों एवं ग्रामीणों को अभियान की जानकारी प्रदान की गई।

यह अभियान महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. श्री सुमन बरवा के मार्गदर्शन एवं डॉ. देवराज चैरे के संयोजन में संचालित किया जा रहा है। अभियान के अंतर्गत क्षेत्र के हायर सेकेंडरी विद्यालयों में संपर्क के साथ-साथ ग्राम पंचायतों में सामुदायिक बैठकों के माध्यम से ग्रामीण समुदाय से सीधा संवाद स्थापित किया जा रहा है। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया, महाविद्यालय में उपलब्ध शैक्षणिक एवं सह-शैक्षणिक सुविधाओं तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अंतर्गत लागू नवीन प्रावधानों जैसे बहुविषयक

शिक्षा, क्रेडिट बैंक, कौशल आधारित पाठ्यक्रम, विषय चयन आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। कैरियर काउंसलिंग सत्र के दौरान विद्यार्थियों को विभिन्न कैरियर विकल्पों, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी, नैतिक शिक्षा, उच्च शिक्षा के अवसरों, रोजगार संभावनाओं एवं कौशल आधारित शिक्षा के महत्व से अवगत कराया गया। साथ ही केंद्र एवं राज्य शासन की छात्रवृत्ति योजनाओं, प्रोत्साहन योजनाओं, निःशुल्क सहायता योजनाओं तथा मध्यप्रदेश शासन की विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी भी प्रदान की गई। सामुदायिक बैठकों का मुख्य उद्देश्य यह है कि क्षेत्र के सभी विद्यार्थियों का बारहवीं के पश्चात महाविद्यालयों में शत-प्रतिशत प्रवेश सुनिश्चित हो तथा कोई भी विद्यार्थी जानकारी के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित न रहे। कार्यक्रम में ग्राम पंचायत बल्हारपुर के सरपंच श्री सेवन काठेकर, सचिव राजेन्द्र बागारे, पंच ज्ञानिराम कुवरे एवं ग्राम पंचायत कटंगझरी की सरपंच श्रीमती कविता हटवार सहित गणमान्य नागरिक श्री नवीन पटले, श्री रामप्रसाद अजीत, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, स्व-सहायता समूह की सदस्याएँ एवं बड़ी संख्या में ग्रामीण उपस्थित रहे।

वैनगंगा में ज़हर घोलने का आरोप: एमकेपीएस फ़ूड एक्सपोर्ट पर प्रशासन की जांच, रसूख और राजनीति के दावे से गरमाया गोपालगंज

...तो क्या सिवनी के जिम्मेदार धृतराष्ट्र है?

सिवनी जिले के गोपालगंज में वैनगंगा नदी को कथित रूप से दूषित करने का मामला अब प्रशासनिक कार्रवाई और सियासत के केंद्र में आ गया है। एमकेपीएस फ़ूड एक्सपोर्ट कंपनी पर मिल से

निकलने वाले दूषित व कैमिकल युक्त पानी को सीधे नदी में छोड़ने के आरोपों के बाद प्रशासन ने जांच टीम गठित कर दी है। प्रारंभिक तथ्यों में कंपनी द्वारा दीवार में छेद कर पानी नदी में मिलाने की बात सामने आई है,

जिसे ग्रामीणों और मानव जीवन के लिए ‘प्राणघातक’ बताया जा रहा है। जांच जारी है, लेकिन इस बीच कंपनी मालिक के कथित रसूख और पंचायत की भूमिका पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

सिवनी | संजय बघेल
rashtrabaan.in

सिवनी जिले की वैनगंगा नदी स्थानीय जीवनरेखा मानी जाती है। सिंचाई, पशुपालन और दैनिक उपयोग के लिए निरभर ग्रामीणों ने लंबे समय से नदी के पानी के रंग, गंध और गुणवत्ता में बदलाव की शिकायतें की थीं। हालिया शिकायतों के बाद प्रशासन हरकत में आया और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) के नेतृत्व में जांच टीम गठित की गई। सूत्रों के अनुसार, प्रारंभिक जांच में यह संकेत मिले हैं कि एमकेपीएस फ़ूड एक्सपोर्ट द्वारा मिल परिसर की दीवार में छेद कर अपशिष्ट जल को सीधे नदी में प्रवाहित किया गया।

प्रशासनिक सूत्रों का कहना है कि इस अपशिष्ट में कैमिकल की मौजूदगी की आशंका है, जो जलीय जीवों के साथ-साथ मानव स्वास्थ्य के लिए भी खतरनाक हो सकती है। हालांकि, अंतिम निष्कर्ष जांच रिपोर्ट और नमूनों की लैब जांच के बाद ही सामने आएंगे। फिलहाल, टीम द्वारा स्थल निरीक्षण, दस्तावेजों की जांच ककी जा रही है।

रसूख और धमकी के आरोप

मामले ने जब तूल पकड़ा तो कंपनी मालिक मुकेश मित्तल के तिलमिला गए। सूत्रों के अनुसार, मित्तल ने कार्रवाई को



शीतला पटले, कलेक्टर निष्पक्ष कार्यवाही की आस।



एमकेपीएस फ़ूड एक्सपोर्ट मिल : जीवन के लिए बनी दानव।



मुकेश मित्तल, कंपनी मालिक राजनीति और प्रशासन जेब में!

प्रशासन की कार्रवाई और आगे की राह

प्रशासन का कहना है कि जांच निष्पक्ष और नियमों के अनुसार की जाएगी। यदि आरोप सही पाए जाते हैं, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम सहित संबंधित धाराओं में कड़ी कार्रवाई संभव है। जिसमें जुर्माना, संवादन

पर रोक और सुधारात्मक उपाय शामिल हो सकते हैं। साथ ही, पंचायत और संबंधित अधिकारियों की भूमिका की भी समीक्षा की जा सकती है। यह मामला केवल एक कंपनी तक सीमित

नहीं है, यह संदेश देता है कि पर्यावरणीय नियमों की अनदेखी और कथित रसूख के भरोसे जनजीवन से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वैनगंगा को बचाने की यह लड़ाई अब प्रशासन की साख और

स्थानीय शासन की जवाबदेही की भी परीक्षा बन चुकी है। जांच रिपोर्ट का इंतजार है, जो तय करेगी कि आरोप सच हैं या नहीं, और दोषियों पर कानून का डंडा चलेगा या नहीं।

लेकर यह कहने की बात कही कि 'प्रशासन और राजनीति मेरी जेब में है' और किसी अधिकारी के सख्त कदम उठाने पर उसके तबादले की ताकत रखने का दावा किया गया है। हालांकि, इन दावों की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसे आरोपों ने प्रशासन की निष्पक्षता और राजनीतिक संरक्षण पर सवाल खड़े कर

दिए हैं। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वर्षों से मिल से दूषित पानी छोड़े जाने की शिकायतें होती रहीं, पर प्रभावशाली संरक्षण के चलते कार्रवाई नहीं हुई। शायद ग्रामीणों की महीनो पहले की गई शिकायत शोभा की सुपारी बनने की वजह भी मुकेश मित्तल के रसूख की वजह है।

पंचायत की भूमिका पर सवाल

इस पूरे प्रकरण में ग्राम पंचायत गोपालगंज की भूमिका भी कटघरे में है। आरोप है कि स्थानीय स्तर पर वर्षों से दूषित पानी के निस्तारण की समस्या के बावजूद सरपंच और सचिव ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया। पंचायत पर यह भी सवाल है कि बिना प्रभावी अपशिष्ट जल प्रबंधन योजना के मिल को संचालन की अनुमति कैसे दी

गई। ग्रामीणों का कहना है कि यदि समय रहते निगरानी और आपत्ति दर्ज होती, तो नदी की यह हालत न होती। आरोपों के बीच यह भी चर्चा है कि बिना आर्थिक लाभ के ऐसी अनदेखी संभव नहीं दिखती। हालांकि, पंचायत प्रतिनिधियों की ओर से इन आरोपों पर अब तक कोई औपचारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

खौफ के सौदागरों पर पुलिस का हंटर

डूंडासिवनी में आतंक मचाने वाले 11 गुंडे सलाखों के पीछे!

सिवनी | संवाददाता
rashtrabaan.in

अपराधियों के लिए काल और आम जनता के लिए ढाल बनी सिवनी पुलिस ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जिले में गुंडराज के लिए कोई जगह नहीं है। पुलिस अधीक्षक सुनील मेहता के सख्त निर्देशों पर अमल करते हुए डूंडासिवनी पुलिस ने खोफ फैलाने वाले 11 बदमाशों को गिरफ्तार कर जेल की कालकोठी में पहुंचा दिया है।

मामला यह है कि बीती 6 जनवरी को भवानी चौक, टैगोर वार्ड में उस वक्त अफरा-तफरी मच गई। जब फरहान खान, हाकिम खान और इमरान खान जैसे अराजक तत्व अपने 20-25 साथियों के साथ हाथों में तलवारें, डंडे और लोहे की रॉड लेकर ममता यादव के घर में घुस गए। इन हमलावरों ने न केवल मां-बहन की भद्दी गालियां दीं, बल्कि घर में



जमकर तोड़फोड़ की। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार हमलावर इतने आक्रोशित थे कि अगर प्रार्थिका का बेटा हाथ लग जाता तो वे उसकी जान लेने पर उतारू थे।

कानून का डंडा, अपराधियों में खौफ पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की सुसंगत धाराओं के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें सीधे जिला जेल भेज दिया गया। इस साहसिक कार्यवाही में निरीक्षक चैनसिंह उड्डेक, सजिन बालकृष्ण त्रिगाम, संजय बघेल और पूरी टीम की अहम भूमिका

पुलिस का एक्शन अवतार

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक दीपक मिश्रा एवं सी.एस.पी. सिवनी श्रद्धा सोनकर के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी चैनसिंह उड्डेक ने तत्काल मोर्चा संभाला। पुलिस की स्पेशल टीम ने घेराबंदी कर दबिश दी और आतंक का पर्याय बने 11 आरोपियों को धर दबोचा। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में मो. जैद खान (19), अरसिल खान (22), रहबर खान (19), इमरान खान (24), फखान (24), इमरान (24), जुनेद (20), आदिल (22), अनस (20), अरमान उर्फ रिहान (18) और अयाज खान उर्फ पिंटू (20) शामिल हैं।

रही। साथ ही पुलिस ने चेतावनी देते हुए कहा कि पुलिस प्रशासन ने साफ कर दिया है कि शांति भंग करने वाले और हथियारों के दम पर खोफ पैदा करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा।

सिवनी | संवाददाता

rashtrabaan.in

जिले के दवा बाजार में उस वक्त हड़कंप मच गया जब खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग ने नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले मेडिकल स्टोर्स पर सर्जिकल स्ट्राइक कर दी। औषधि निरीक्षक की पैनी नजरों से लापरवाह दुकानदार बच नहीं पाए और देखते ही देखते 07 दुकानों के लाइसेंस लॉक कर दिए गए।

किसकी कितनी

‘खुराक’ बंद?

दवाइयों के रिकॉर्ड में हेराफेरी और नियमों को टेंगे पर रखने वाले इन सेंटर्स को विभाग ने कड़



सबक सिखाया है। श्री मेडिकल स्टोर मेहरा पिपरिया: सबसे भारी गाज, 20 दिनों के लिए दुकान बंद, जय मां दुर्गा राय मेडिकल चमारी छपारा : 07 दिनों का वनवास, श्री आशुतोष मेडिकल छपारा : 05 दिनों के लिए शटर डाउन, साहू मेडिकल छपारा : 03 दिनों के लिए कामकाज ठप, संजीवनी मेडिकल केवलारी 07 दिनों के लिए ताला लटका, अमन मेडिकल केवलारी 05 दिनों की छुट्टी तो लविश मेडिकल ओषे टा बरघाट : 03

भारत पर्व के आयोजन के लिए नोडल अधिकारी नियुक्त

सिवनी | संवाददाता
rashtrabaan.in

शासन के निर्देशानुसार कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा आगामी 26 जनवरी 2026 को गणतंत्र दिवस की शाम जिला मुख्यालय सिवनी में लोकतंत्र के लोक उत्सव ‘भारत पर्व’ के आयोजन के मद्देनजर भारत पर्व के आयोजन के लिए मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत श्रीमती अंजली शाह को

नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। कार्यक्रम के सफल आयोजन के लिए आवश्यक सहयोग एवं समस्त स्थानीय व्यवस्थाओं के लिए आहरण एवं व्यय वितरण अधिकारी के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी एस एस कुमरे को प्रभार सौंपा गया है। वहीं, अन्य आवश्यक सहयोग एवं कार्यक्रम संचालन के लिए सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास सिवनी को अधिकृत किया गया है।

बबरिया तालाब से मोटर लगाकर पानी लेने पर प्रतिबंध

सिवनी | संवाददाता
rashtrabaan.in

नगरपालिका परिषद सिवनी द्वारा सर्वसाधारण एवं किसानों से अपील की गई है कि नगरपालिका स्वामित्व बबरिया तालाब में फसल सिंचाई हेतु मोटर लगाकर पानी न लिया जाए। बताया गया है कि तालाब से लगातार पानी निकाले जाने के कारण जल स्तर में कमी आ रही है, जिससे पूर्व वर्ष ग्रीष्म ऋतु में जल संकट की स्थिति निर्मित हुई थी।

नगरपालिका द्वारा आगामी ग्रीष्म ऋतु को दृष्टिगत रखते हुए बबरिया तालाब का पानी पेयजल उपयोग हेतु सुरक्षित रखा जाना आवश्यक है, ताकि नगरवासियों को गर्मी के मौसम में पर्याप्त

पेयजल उपलब्ध कराया जा सके। इसी उद्देश्य से तालाब से सिंचाई के लिए पानी लेना पूर्णतः प्रतिबंधित किया गया है। नगरपालिका ने किसानों से सहयोग की अपील करते हुए कहा है कि यदि किसी भी किसान द्वारा बबरिया तालाब में अवैध रूप से मोटर लगाकर पानी लिया जाता है, तो संबंधित किसान की मोटर जब्त की जाएगी तथा नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जाएगी। उक्त कार्यवाही की संपूर्ण जिम्मेदारी संबंधित किसान की स्वयं की होगी। नगरपालिका परिषद ने सभी किसानों एवं नागरिकों से जनहित में सहयोग करने एवं जल संरक्षण में सहभागी बनने का अनुरोध किया है।

8 जनवरी को सिवनी में जलापूर्ति रहेगी प्रभावित

नागरिकों से एक दिवस का जल संग्रह की अपील

सिवनी | संवाददाता
rashtrabaan.in

मुख्य नगरपालिका अधिकारी सिवनी द्वारा जानकारी देकर बताया गया कि पुरानी नवीन जलावर्धन योजना अंतर्गत बबरिया प्लांट में सी.एल.एफ. की सफाई कार्य चलते 8 जनवरी 2026 को सुबह 9 बजे से शाम 6 बजे तक डायरेक्ट एवं

टंकी जलापूर्ति प्रभावित रहेगी। इस दौरान नगर की पानी टैंकियों में भराव कार्य बंद रहेगा। उन्होंने बताया कि इसी तरह 9 जनवरी को डायरेक्ट एवं टंकी से जुड़े क्षेत्रों में पेयजल आपूर्ति आंशिक रूप से की जाएगी। असुविधा से बचने के लिए कम से कम एक दिन का पानी संग्रहित रखने की अपील शहर के नागरिकों से की गई है।

कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले की अध्यक्षता में विशेष डीलसीसी बैठक संपन्न

सिवनी। सोमवार 05 जनवरी को कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभागार में विशेष जिला स्तरीय समन्वय समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक में अपर कलेक्टर सी.एल. चनाप एवं सुश्री सुनीता खंडायत, लीड बैंक अधिकारी प्रवीण कुमार दिसौरिया, जिला समन्वयक, समस्त बैंकों के प्रतिनिधि तथा संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में विभिन्न शासकीय योजनाओं के लक्ष्य एवं प्रगति की समीक्षा की गई।

इस अवसर पर कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले ने बताया कि उद्यानिकी विभाग की पीएमएफएमई योजना, अनुसूचित जनजाति विभाग की टट्टया मामा आर्थिक कल्याण योजना, अंत्योदय/अंतव्यासाई विभाग की डॉ. भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना, पशुपालन विभाग की डेयरी केसीसी एवं डॉ. भीमराव कामधेनु योजना, तथा मत्स्य विभाग की केसीसी योजना की प्रगति अपेक्षानुसार संतोषजनक नहीं पाई गई।

जिला स्तरीय जनसुनवाई में 182 आवेदन प्राप्त

सिवनी | संवाददाता
rashtrabaan.in

प्रत्येक मंगलवार को कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में आयोजित होने वाली जिलास्तरीय जनसुनवाई कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। जनसुनवाई में कुल 182 आवेदन प्राप्त हुए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर श्री सी.एल. चनाप, अपर कलेक्टर सुश्री सुनीता खंडायत सहित विभिन्न विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे। वहीं सभी अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं विकासखंड स्तरीय अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जनसुनवाई से जुड़े।

जिलास्तरीय जनसुनवाई में तहसील बरघाट अंतर्गत ग्राम खुसीपारकला निवासी प्रतीमा



कोरेमारे द्वारा कले याणी विवाह सहायता योजना का लाभ दिलाये जाने विषयक, तहसील सिवनी अंतर्गत ग्राम मुणे डई निवासी लक्ष्मी मण भजेकर द्वारा मकान एवं खेत का सीमांकन कराये जाने विषयक, ग्राम भोंगाखेडा थाना बंडोल निवासी गोबंदी गिरी द्वारा समग्र आईडी में नाम दर्ज कराये जाने विषयक, तहसील लखनादौन

अंतर्गत ग्राम भजिया निवासी कोमलचंद गोले हानी द्वारा शासकीय भूमि पर हुए अतिक्रमण को हटायें जाने विषयक, ग्राम बांद्रा थाना बंडोल निवासी सुरेंद्र भलावी द्वारा माचागोरा बांध में अधिग्रहित कर नहर खोदे जाने पर मुआवजा राशि दिलाये जाने विषयक, ग्राम बांकी थाना बंडोल निवासी नारायण द्वारा नवे शा सुधार किये जाने

विषयक, जनतानगर सिवनी निवासी सहजाद खान द्वारा जे-म प्रमाण पत्र प्रदाय किये जाने विषयक, कबीर वार्ड डूंडासिवनी निवासी कमल सिंह धुर्वे द्वारा आबादी भूमि में बने मकान का पट्टा दिलाये जाने विषयक, तहसील धनौरा अंतर्गत ग्राम सुनवारा निवासी रेवाराम प्रजापति द्वारा आवास योजना की राशि दिलाये जाने विषयक, तहसील छपारा निवासी शंकर लाल डहेरिया द्वारा खेत में आने जाने के लिए रास्ते ता दिलाये जाने विषयक, तहसील छपारा अंतर्गत ग्राम बिजना निवासी नेवालाल उड्डेक द्वारा आर्थिक सहायता राशि दिलाये जाने विषयक, तहसील बरघाट अंतर्गत ग्राम पिपरिया थाना अरी निवासी इमनबाई पटले द्वारा वृद्धापेंशन योजना का लाभ दिलाये जाने

विषयक, रानी दुर्गावती वार्ड सिवनी निवासी राजकुमार सनोडिया द्वारा नाली की सफाई कराये जाने विषयक, तहसील धनौरा अंतर्गत ग्राम नाई पिपरिया निवासी सोनल नामदेव द्वारा बाल आशिर्वाद योजना का लाभ दिलाये जाने विषयक, तहसील केवलारी अंतर्गत ग्राम बगलई निवासी ज्योति साहू द्वारा धारणाधिकार अंतर्गत पट्टा दिलाये जाने विषयक, तहसील धनौरा अंतर्गत समरे त ग्राम बरबसपुर निवासी द्वारा ग्राम में स्थित सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटायें जाने विषयक, सहित कुल 182 आवेदन प्राप्त हुए। प्राप्त आवेदनों पर नियमानुसार कार्यवाही कर शीघ्र निराकरण किये जाने के निर्देश कलेक्टर श्रीमती शीतला पटले द्वारा संबंधित विभागीय अधिकारियों को दिये गये।

कम्प्यूटर वर्ल्ड सेल्स एंड सर्विस

लैपटॉप, कम्प्यूटर, सी.सी.टी.वी कैमरा, होम थियेटर, प्रिंटर, लेमिनेशन, फोटो कॉपियर, नेटवर्किंग, प्रोजेक्टर, कॉर्टरज रिफ्लिंग



संपर्क- वैनगंगा कॉम्प्लेक्स, बस स्टैंड, सिवनी, मो.न.-9302833332



अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें

 **7898723789**

Infront of Reliance Petrol-pump,
Jabalpur Road, Jyarat Naka, Seoni
480661 (M.P)

